www.sanjanabharati.com
दिल्ली और गौतम बुद्ध नगर से प्रकाशित। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड व उत्तराखंड में प्रसारित
facebook.com/Sanjanabharati

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

संजना भारती

RNI No. : DELHIN/2016/70240

आपका भरोसा, हमारी ताकत

2 जानें प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, राजनाथ...
3 20 सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति की बैठक में...
4 नेशन के लिए सुलह अभियान जिला करनाल में...

वर्ष: 9 | अंक: 277 | दिल्ली, गुरुवार, 31 जुलाई 2025 | पृष्ठ संख्या: 4 | मूल्य: 1 रुपया

कांग्रेस ने पीओके पाकिस्तान को दिया लेकिन भाजपा सरकार उसे वापस लेगी: अमित शाह

नई दिल्ली (एजेन्सी)। गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में पहलगाम में आतंकवादी हमले के जवाब में भारत के मजबूत, सफल एवं निर्णायक ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष चर्चा में बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने पीओके (पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर) पाकिस्तान को दिया लेकिन भाजपा सरकार उसे वापस लेगी। पहलगाम हमले पर बोलते हुए शाह ने कहा कि इस तरह के बर्बर अपराध कभी नहीं हुए, जहां लोगों को महिलाओं, बच्चों के सामने मारने से पहले उनका धर्म पूछा गया। उन्होंने कहा कि पहले हम सिर्फ डोजियर भेजते रहे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने उन्हें (पाकिस्तान को) एयरस्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक से जवाब दिया...खौफ पैदा हो गया।

अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर यह कांग्रेस के राज में हुआ होता, तो विदेश मंत्रालय बयान जारी करता। हम ब्रह्मोस मिसाइल भेजते हैं, डोजियर नहीं। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ने देश पर सबसे लंबे समय तक शासन किया, लेकिन प्रमुख सुरक्षा खतरों पर कार्रवाई करने में विफल रही। उन्होंने कहा, "हमें आतंकवाद, नक्सलवाद और पूर्वोत्तर में उग्रवाद का सामना करना पड़ा-और उन्होंने कुछ नहीं किया।" शाह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर कोई घोषित युद्ध नहीं था, बल्कि भारत के आत्मरक्षा के अधिकार के तहत एक प्रतिक्रिया थी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने युद्धविराम की भीख माँगी और हमने रोक दिया। उन्होंने आगे कहा कि यह कार्रवाई संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुरूप थी। अमित शाह ने संसद में कांग्रेस पर तीखा हमला बोला और उस पर जम्मू-कश्मीर में अलगाववाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। शाह ने कहा कि अनुच्छेद 370 और 35ए को कांग्रेस ने समर्थन दिया और इसी ने घाटी में अलगाववादी सोच को जन्म दिया। उन्होंने आगे कहा कि यही अलगाववाद बाद में स्वतंत्र राज्य की मांग में बदल गया, जो बाद में कश्मीर में आतंकवाद का आधार बन गया। उन्होंने कहा, "कांग्रेस की तुष्टिकरण की राजनीति के कारण ही इन सभी आतंकवादी संगठनों को सक्रिय होने दिया गया।"

शाह ने राज्यसभा में कहा कि सरकार ने जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद को समर्थन देने वाले तंत्र को व्यवस्थित रूप से ध्वस्त कर दिया है। शाह ने कहा, "जमात-ए-इस्लामी जैसे समूहों ने एक गहरी जड़ें जमा ली थीं जिसने अलगाववाद और कट्टरपंथ को वैधता प्रदान की। वह तंत्र अब अस्तित्व में नहीं है।" जमात-ए-इस्लामी (खीक), एक सामाजिक-धार्मिक समूह, जिस पर 2019 में गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम के तहत प्रतिबंध लगा दिया गया था, पर लंबे समय से घाटी में चरमपंथी विचारधारा को बढ़ावा देने और अलगाववादी उद्देश्यों का समर्थन करने का आरोप लगाया जाता रहा है। इसके हिज्बुल मुजाहिदीन के साथ घनिष्ठ वैचारिक संबंध थे और इसे धार्मिक संस्थानों, तथाकथित स्कूलों और धर्मार्थ संस्थाओं के माध्यम से युवाओं को कट्टरपंथी बनाने में सहायक माना जाता था।

सिंदूर तो उजड़ गया फिर ऑपरेशन का नाम सिंदूर क्यों?-जया बच्चन

नई दिल्ली (एजेन्सी)। समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन ने बुधवार को ऑपरेशन सिंदूर के नाम को लेकर सरकार पर सवाल उठाया और कहा कि पहलगाम आतंकी हमले में जिन महिलाओं के पति मारे गए थे, उनके माथे से सिंदूर मिटा दिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर पर बहस के दौरान राज्यसभा में बच्चन ने कहा, "मुझे आपको (सत्तारूढ़ पार्टी को) ऐसे लेखकों को नियुक्त करने के लिए बधाई देनी चाहिए जो इतने भव्य नाम देते हैं। लेकिन आपने इसका नाम 'सिंदूर' क्यों रखा? जिन महिलाओं के पति मारे गए थे, उनके माथे से सिंदूर मिटा दिया गया है।" भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि सिंदूर शक्ति और क्षमता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि अब पृथ्वीराज चव्हाण अकेले नहीं हैं। जरा सोचिए, यह कैसी मानसिकता है। वे ऑपरेशन महादेव के नाम पर सवाल उठाते हैं और इसे सांप्रदायिक कहते हैं... जया बच्चन जी, आतंकवादियों ने महिलाओं का सिंदूर मिटा दिया। सिंदूर शक्ति और क्षमता का प्रतीक है। यही संदेश देने के लिए इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया... यह दुखद है। कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने पहले भाजपा पर धार्मिक प्रतीकों के नाम पर अभियान चलाने का आरोप लगाया था।

दिल्ली में अब तक का सबसे भव्य शहीदी दिवस का हुआ आयोजन

संजना भारती संवाददाता

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार 9वें सिख गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस को लाल किले में आयोजित एक भव्य 3 दिवसीय कार्यक्रम के माध्यम से मनाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में इस कार्यक्रम की तैयारियों पर उच्च-स्तरीय बैठक हुई। बैठक में दिल्ली के कला एवं संस्कृति मंत्री कपिल मिश्रा, पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा, प्रमुख सिख नेता, धार्मिक संगठन और समुदाय के अन्य गणमान्य लोग शामिल हुए।

बैठक में पद्मश्री एवं राज्यसभा सांसद विक्रमजीत सिंह, पूर्व सांसद तरलोचन सिंह, एसएस कोहली, चरण सिंह (पंजाब एंड सिंध बैंक), डीएसजीएमसी चेयरमैन श्री हरमीत सिंह कालका तथा दिल्ली-एनसीआर व अन्य राज्यों के गुरुद्वारा कमेटी सदस्य मौजूद रहे।

सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, श्री गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिवस भारत के सर्वोच्च आदर्शों-आजादी, न्याय और करुणा-का प्रतीक है। यह कार्यक्रम दिल्ली की ओर से उन मूल्यों के प्रति दिल से दी गई श्रद्धांजलि है। हमारा उद्देश्य इतिहास को याद करना ही नहीं बल्कि गुरु साहिब का शाश्वत संदेश हर पीढ़ी तक पहुँचाना है। उन्होंने कहा कि यह आयोजन देश का सबसे बड़ा और दिल्ली का पहला ऐसा कार्यक्रम होगा जहां सभी धर्मों के लोग मिलकर गुरु साहिब के सर्वोच्च बलिदान को सम्मान देंगे।

वरिष्ठ सिख नेता और पर्यावरण मंत्री श्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, पहली बार दिल्ली में गुरु साहिब के जीवन और शिक्षाओं पर आधारित इतना बड़ा और इमर्सिव आयोजन होगा। लाल किले में लाइट एंड साउंड शो आयोजित किया जाएगा, जिसमें पूरी तरह सिख इतिहास और दर्शन को दर्शाया जाएगा। उन्होंने आगे कहा, छात्रों के लिए वर्चुअल रियलिटी (वीआर) अनुभव की शुरूआत भी की जाएगी, जिससे वे गुरु साहिब के जीवन के अहम क्षणों को महसूस कर सकेंगे। कला एवं संस्कृति विभाग लगातार समुदाय और गुरुद्वारा समितियों के सुझावों पर काम कर रहा है। जून में हुई बैठक में कई विचार रखे गए थे, जिनके आधार पर यह कार्यक्रम डिजाइन हो रहा है। सरकार ने जौनापुर में बन रहे मियावाकी जंगल को गुरु साहिब को समर्पित करने का भी निर्णय लिया है। श्री सिरसा ने यह भी बताया कि गुरु साहिब की शिक्षाओं को इस कार्यक्रम के दौरान विभिन्न भाषाओं में जनता तक पहुँचाया जाएगा ताकि उनके आध्यात्मिक और दार्शनिक योगदान को व्यापक रूप से समझा जा सके।

दिल्ली-मुंबई मार्ग के मथुरा-कोटा रेल खंड पर स्थापित हुआ कवच 4.0

संजना भारती/विज्ञप्ति द्वारा

गोरखपुर। भारतीय रेल द्वारा स्वदेशी रेल सुरक्षा प्रणाली कवच 4.0 को उच्च घनत्व (हाई डेंसिटी) वाले दिल्ली-मुम्बई मार्ग के मथुरा-कोटा रेलखंड पर स्थापित कर दिया गया है। यह देश में रेलवे सुरक्षा प्रणालियों के आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रेलवे ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के 'आत्मनिर्भर भारत' दृष्टिकोण से प्रेरित होकर कवच ऑटोमैटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम को स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित किया है। कवच 4.0 एक अत्याधुनिक तकनीकी प्रणाली है। इसे जुलाई, 2024 में अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन (आर.डी.एस.ओ.) द्वारा स्वीकृति दी गई थी। कई विकसित देशों को ऐसी ट्रेन सुरक्षा प्रणाली को विकसित और स्थापित करने में 20 से 30 वर्ष लग गए। कोटा-मथुरा रेलखंड पर कवच 4.0 बहुत कम समय में स्थापित किया गया है, जो कि एक बड़ी उपलब्धि है। इसी क्रम में, स्वदेशी रूप से विकसित कवच स्वचालित ट्रेन सुरक्षा (ए.टी.पी.) प्रणाली को पूर्वोत्तर रेलवे के 1,441 रूट किमी. पर लगाने का कार्य रेल मंत्रालय द्वारा रु. 492.21 करोड़ की लागत से स्वीकृत किया गया है।

कवच के इंस्टालेशन को प्राथमिकता प्रदान करते हुये इसे पूर्वोत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल पर लखनऊ जं.-मानक नगर, लखनऊ जं.-मल्हौर, बाराबंकी जं.-बुढ़वल जं., सीतापुर सिटी-बुढ़वल जं. एवं बुढ़वल जं.-गोरखपुर कैंट; वाराणसी मंडल पर गोरखपुर कैंट-गोल्डिनगंज, गोरखपुर कैंट-वाल्मीकिनगर रोड, भटनी जं.-वाराणसी जं., वाराणसी जं.-प्रयागराज जं. एवं औंड़िहार जं.-छपरा जं.; तथा इज्जतनगर मंडल पर रावतपुर-फर्रुखाबाद जं., फरुर्खाबाद जं.-कासगंज जं. एवं कासगंज जं.-मथुरा जं. खंडों पर कवच का कार्य स्वीकृत है।

प्रथम चरण में पूर्वोत्तर रेलवे के 558 रूट किमी. पर कवच लगाने का कार्य किया जायेगा, जिसमें लखनऊ मंडल के सीतापुर सिटी-बुढ़वल जं., बुढ़वल जं.-गोरखपुर कैंट, मानक नगर-लखनऊ जं.-मल्हौर एवं बाराबंकी-बुढ़वल जं.; तथा वाराणसी मंडल के गोरखपुर कैंट-गोल्डिनगंज खंड सम्मिलित हैं।

इस रेलवे पर टावर कार्य एवं कवच उपकरण हेतु दो निविदाओं के माध्यम से कवच स्थापित करने का कार्य किया जायेगा। वर्तमान में मुख्य मार्ग छपरा-बाराबंकी में टावर लगाने का कार्य प्रगति पर है तथा गोरखपुर कैंट-छपरा ग्रामीण के

मध्य टावर लगाने का निविदा दिया गया है। स्वतंत्रता के बाद 60 वर्षों तक देश में अंतरराष्ट्रीय मानकों की उन्नत ट्रेन सुरक्षा प्रणालियों को स्थापित नहीं किया गया। अब कवच प्रणाली को हाल ही में चालू किया गया है, ताकि ट्रेन और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

भारतीय रेल अगले 06 वर्षों के भीतर देशभर के विभिन्न रेल मार्गों पर कवच 4.0 को स्थापित करने की तैयारी कर रहा है। अब तक 30,000 से अधिक लोगों को कवच प्रणाली पर प्रशिक्षित किया जा चुका है।

भारतीय रेल सिगनल इंजीनियरिंग एवं दूरसंचार संस्थान (इरिसेट-आई.आर.आई.एस.ई.टी.) ने ए.आई.सी.टी.ई. से मान्यता प्राप्त 17 इंजीनियरिंग कॉलेजों, संस्थानों, विश्वविद्यालयों के साथ समझौता किया है, ताकि बी.टेक. पाठ्यक्रम में कवच को शामिल किया जा सके। कवच से लोको पायलटों को मदद मिलेगी: ब्रेक प्रभावी रूप से लगाने में और कोहरे जैसी कम दृश्यता की स्थिति में सिग्नल देखने के लिए बाहर देखने की आवश्यकता नहीं होगी। उन्हें सारी जानकारी केबिन के अंदर लगे डैशबोर्ड पर दिखाई देगी। भारतीय रेल हर साल सुरक्षा संबंधी गतिविधियों पर 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक निवेश करता है। कवच ऐसी कई पहलों में से एक है जो ट्रेनों और यात्रियों की सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई हैं। कवच की त्वरित प्रगति और तैनाती का स्तर रेलवे की सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

क्या है कवच?

- कवच एक स्वदेशी रूप से विकसित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है, जिसे ट्रेनों की गति की निगरानी और नियंत्रण करके दुर्घटनाओं को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है।
- इसे सेफ्टी इंटिग्रिटी लेवल 4 (एस.आई.एल.-4) पर डिजाइन किया गया है, जो सुरक्षा का सर्वोच्च स्तर है।
- कवच का विकास 2015 में शुरू हुआ। इसे 03 वर्षों तक परीक्षण किया गया।
- तकनीकी सुधारों के बाद इसे पहले दक्षिण मध्य रेलवे में स्थापित किया गया और 2018 में पहला संचालन प्रमाणपत्र मिला।
- दक्षिण मध्य रेलवे में अनुभवों के आधार पर एक उन्नत संस्करण 'कवच 4.0' विकसित किया गया, जिसे मई 2025 में 160 किमी./घंटा तक की गति के लिए मंजूरी दी गई।
- कवच के सभी उपकरण स्वदेशी रूप से निर्मित किए जा रहे हैं।

कवच की जटिलता

कवच एक अत्यंत जटिल प्रणाली है। इसे कमीशन करना किसी टेलीकॉम कम्पनी को खड़ा करने के समान है। इसमें निम्नलिखित उप-प्रणालियां शामिल हैं।

- **आर.एफ.आई.डी. टैग्स:** प्रत्येक 01 किमी. पर और प्रत्येक सिगनल पर लगाए जाते हैं। ये ट्रेन की सटीक स्थिति बताते हैं।
- **टेलीकॉम टावर्स:** हर कुछ किलोमीटर पर ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी और पावर सप्लाई सहित टावर्स लगाए जाते हैं। लोको कवच और स्टेशन कवच लगातार इन टावर्स के जरिए संचार करते हैं।
- **लोको कवच:** ट्रैक पर लगे आर.एफ.आई.डी. टैग्स से जानकारी प्राप्त करता है, उसे टेलीकॉम टावरों तक पहुंचाता है और स्टेशन कवच से रेडियो सूचना प्राप्त करता है। इसे लोको के ब्रेकिंग सिस्टम से भी जोड़ा गया है, ताकि आपात स्थिति में स्वत: ब्रेक लगे।
- **स्टेशन कवच:** प्रत्येक स्टेशन और ब्लॉक सेक्शन पर लगाया जाता है। यह लोको कवच और सिगनल प्रणाली से जानकारी लेकर सुरक्षित गति के लिए निर्देश देता है।
- **ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओ.एफ.सी.):** पूरी प्रणाली को जोड़ने के लिए ट्रैक के साथ-साथ ओ.एफ.सी. बिछाई जाती है, जिससे हाई-स्पीड डेटा कम्युनिकेशन सम्भव होता है।
- **सिगनलिंग सिस्टम:** सिगनलिंग सिस्टम को लोको कवच, स्टेशन कवच, टेलीकॉम टावर आदि से जोड़ा गया है।

इन सभी प्रणालियों को बिना किसी रेल संचालन में व्यवधान के भारी पैसेंजर और माल गाड़ियों की आवाजाही के दौरान स्थापित, जांच और प्रमाणित किया जाता है।

कवच की प्रगति

ऑप्टिकल फाइबर बिछाया गया	-5,856 किमी.
दूरसंचार टावर स्थापित	-619
स्टेशनों पर कवच स्थापित	-708
लोको पर कवच स्थापित	-1,107
ट्रैकसाइड उपकरण स्थापित	-4,001 रूट किमी.

छत पर सोलर पैनल लगाने वाले परिवारों का बिजली बिल आएगा शून्य: नायब सिंह सैनी

संजना भारती संवाददाता

चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि अधिकारियों की टीम गांव-गांव में आकर प्रधानमंत्री मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर पैनल की प्रक्रिया पूरी करवाएगी। सरकार द्वारा अंत्योदय की नीति पर काम करते हुए जिस परिवार की आय 1.80 लाख रुपए से कम है, उसको इस योजना के तहत 2 किलोवाट का सोलर पैनल उपलब्ध करवाया जाएगा। योजना के तहत 70 हजार रुपए केंद्र सरकार द्वारा और बाकी का पैसा प्रदेश सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिस घर पर सोलर पैनल होगा उस घर का बिजली बिल शून्य हो जाएगा। सरकार ने इस वर्ष में एक लाख घरों पर सोलर पैनल लगाने का लक्ष्य रखा है, अभी तक 26 हजार परिवार इस योजना का लाभ ले चुके हैं।

मुख्यमंत्री बुधवार को लाडवा विधानसभा के गांव गुड़ी, जोगी माजरा, बकाली और निवारसी में आयोजित धन्यवादी कार्यक्रम के दौरान बोल रहे थे। इससे पहले, मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी का गांवों में पधारने पर लोगों ने जोरदार स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने गांव के लोगों की समस्याओं को सुना और उनका समाधान करने के लिए मौके पर ही अधिकारियों को निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने गांव गुड़ी में स्वच्छ पेयजल की पाइप लाइन के लिए 23 लाख 4 हजार रुपए, गांव बकाली में 70 लाख 44 हजार रुपए, गांव जोगी माजरा में 22 लाख रुपए देने की घोषणा की। गांव धनौरा जाटान में 2 करोड़ 73 लाख 86 हजार रुपए की लागत से बने खेल स्टेडियम का उद्घाटन भी किया। मुख्यमंत्री ने सभी गांवों में विकास कार्यों के लिए 21-21 लाख रुपए देने की घोषणा करते हुए कहा कि सरपंचो की तरफ से सौंपे गए मांग पत्रों को संबंधित विभागों को भेज कर पूरा करवाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि तीसरी बार सरकार बनने के बाद विकास कार्यों के लिए गांव गुड़ी में 57 लाख, गांव बकाली में 1 करोड़ 40 लाख रुपए और निवारसी में 2 करोड़ 78 लाख रुपए भेजे जा चुके हैं।

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पिछले दिनों बरसात के कारण किसानों की फसलें प्रभावित हुई थी, सरकार ने प्रभावित किसानों के लिए 1334 करोड़ रुपए मुआवजे के तौर पर सीधे उनके खातों में भेजे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार समाज के सभी वर्गों के लिए समान रूप से कार्य कर रही है।

सीएम की अगुवाई में मंत्रालय द्वारा ग्रामीण विकास ब्लॉकों के पुनर्गठन को हरी झंडी

एसबी संवाददाता

चंडीगढ़। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रबंधकीय व्यवस्था और सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए बड़े प्रशासनिक सुधार लाने के उद्देश्य से पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई में मंत्रिमंडल ने आज ग्रामीण विकास ब्लॉकों के पुनर्गठन को हरी झंडी दे दी है, ताकि इन ब्लॉकों को जिलों की सीमाओं के साथ जोड़ा जा सके। इस फैसले से प्रशासनिक दक्षता में व्यापक सुधार होगा। इस बारे में फैसला आज यहां मुख्यमंत्री की अगुवाई में हुई मंत्रिमंडल की बैठक दौरान लिया गया।

यह खुलासा करते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि विकास ब्लॉकों के अधिकार क्षेत्र को संबंधित जिला सीमाओं के अनुसार लाने के लिए पुनर्गठन किया गया है, जिससे संगरूर, मलेरकोटला, फाज़िल्का, फिरोजपुर, साहिबजादा अजीत सिंह नगर

(मोहाली) और पटियाला जिलों को विशेष तौर पर लाभ होगा। इस पुनर्गठन का उद्देश्य ब्लॉक-स्तरीय और जिला-स्तरीय प्रशासन के बीच बेहतर तालमेल को सुनिश्चित करना, ग्रामीण विकास योजनाओं की बेहतर योजना और विकास स्कीमों के लागूकरण को सुचारू बनाना, इसके अलावा प्रशासनिक कामों की अनावश्यक व्यवस्था (ओवरलैप) को खत्म करना है जो अकसर देरी और सुस्त कार्यप्रणाली के कारण बनते थे। पुनर्गठन की प्रक्रिया के समय मौजूदा प्रशासनिक सीमाओं और क्रियाशील जरूरतों की गहराई से जांच की गई है।

प्रवक्ता ने आगे बताया कि पुनर्गठन के समय सभी जरूरी कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रियाओं का पालन सुनिश्चित किया गया है। इस कदम से राज्य सरकार का उद्देश्य जिला स्तर पर योजना और निगरानी विधियों को मजबूत करना, ब्लॉक और जिला-स्तरीय डेटा और निर्णय लेने की निर्बाध एकीकरण को समर्थ बनाना, नागरिकों और पंचायती राज संस्थाओं के लिए सेवाओं तक पहुंच को आसान बनाना और केंद्र व राज्य आधारित ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की दक्षता में और सुधार करना है। पुनर्गठित किए गए विकास ब्लॉक सरकारी गजट में अधिसूचना प्रकाशित होने पर अमल में आ जाएंगे।

संक्षिप्त समाचार

धर्मांतरण पर देशभर में लगे प्रतिबंध! विहिप ने केंद्र से मांगा कड़ा कानून

नई दिल्ली (एजेन्सी)। तस्करी और धर्मांतरण के आरोप में केरल की दो ननों की छत्तीसगढ़ में गिरफ़्तारी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए विश्व हिंदू परिषद के महासचिव सुरेंद्र जैन ने बुधवार को केंद्र सरकार से धर्मांतरण पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक कानून लाने का आग्रह किया। एएनआई से बात करते हुए, जैन ने आरोप लगाया कि चर्च पर मानव तस्करी के आरोप लगाए गए हैं और अवैध धर्मांतरण को रोका जाना चाहिए। जैन ने एएनआई को बताया कि यह पहली बार नहीं है जब ये आरोप लगाए गए हैं...चर्च पर मानव तस्करी जैसे आरोप लंबे समय से लगते रहे हैं। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उनका समर्थन नहीं किया जाना चाहिए। सेवा की आड़ में वे जो अवैध धंधा चला रहे हैं, उसे रोका जाना चाहिए... हम केंद्र सरकार से अपील करते हैं कि यह कानून (धर्मांतरण विरोधी कानून) कुछ राज्यों में लागू है, लेकिन इसका नेटवर्क व्यापक और देशव्यापी है। इसलिए, धर्मांतरण पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक राष्ट्रव्यापी कानून लाया जाना चाहिए। उन्होंने आगे दावा किया कि गिरफ़्तारी के बाद एक "हिंदू-विरोधी माहौल" सक्रिय हो गया और उन्होंने इसका विरोध करने के लिए कांग्रेस की आलोचना की। यह पाया गया कि वे मानव तस्करी और अवैध धर्मांतरण के अवैध धंधे में शामिल थीं। जैसे ही ननों की गिरफ़्तारी हुई और जाँच शुरू हुई, हिंदू-विरोधी माहौल तुरंत सक्रिय हो गया।

सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने मणिपुर का किया दौरा

मणिपुर (एजेन्सी)। थल सेनाध्यक्ष (सीओएएस) जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने बुधवार को मणिपुर की मौजूदा सुरक्षा स्थिति और राज्य में तैनात असम राइफल्स तथा सेना की सैन्य संरचनाओं की परिचालन तैयारियों की समीक्षा के लिए एक दिवसीय दौरा किया। इस यात्रा ने क्षेत्र में स्थिरता और विकास के लिए भारतीय सेना की दृढ़ प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। अपनी यात्रा के दौरान, सीओएएस को जमीनी हालात और शांति एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से चल रही पहलों की जानकारी दी गई। उन्होंने सैनिकों की परिचालन तैयारियों की समीक्षा की और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में उनके उच्च व्यावसायिकता, लचीलेपन और समर्पण की सराहना की। जनरल द्विवेदी ने मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला से भी मुलाकात की और सुरक्षा एवं विकास से जुड़े मामलों पर चर्चा की। बैठक में क्षेत्र में शांति और प्रगति को बढ़ावा देने में नागरिक प्रशासन और सशस्त्र बलों के बीच सहयोगात्मक प्रयासों पर प्रकाश डाला गया। इसके बाद, सेना प्रमुख खुमान लम्पक स्टेडियम में डूरंड कप के 134वें संस्करण के एक मैच का अवलोकन करेंगे, जो दो साल बाद इम्फाल में इस टूर्नामेंट की वापसी का प्रतीक है। मैच से पहले होने वाले समारोह में एक जीवंत सांस्कृतिक कार्यक्रम और सैन्य प्रदर्शन होंगे, जो मणिपुर की समृद्ध विरासत और सशस्त्र बलों के गौरव को प्रदर्शित करेंगे।

मनसा देवी मंदिर में दर्शन के नियम बदले, भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा पर जोर

हरिद्वार (एजेन्सी)। हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में हुई दुखद भगदड़ के बाद, जिसमें आठ लोगों की मौत हो गई और 30 घायल हो गए, ज़िला प्रशासन ने पहाड़ी पर स्थित इस प्रसिद्ध मंदिर और पास के चंडी देवी मंदिर में सुरक्षा उपायों की व्यापक समीक्षा शुरू कर दी है। मंगलवार (29 जुलाई) को मंदिर प्रबंधन और ज़िला अधिकारियों की एक संयुक्त बैठक हुई जिसमें दीर्घकालिक भीड़ नियंत्रण रणनीतियों पर चर्चा की गई। पुलिस अधीक्षक पंकज गैरोला ने घोषणा की कि मंदिर के रास्तों पर भीड़भाड़ कम करने के लिए श्रद्धालुओं के लिए एकतरफा आवागमन व्यवस्था पर विचार किया जा रहा है। इसके अलावा, मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या मंदिर की क्षमता से अधिक न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए सीमित और क्रमिक प्रवेश व्यवस्था लागू की जाएगी। विशेष अवसरों और त्योहारों पर, प्रवेश और निकास के मार्गों को अलग-अलग करने के लिए ज़िग-ज़ैग मार्ग व्यवस्था लागू की जाएगी, साथ ही भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस बल की तैनाती भी बढ़ाई जाएगी। विशेष अवसरों और त्यौहारों पर, प्रवेश और निकास के मार्गों को अलग करने के लिए ज़िग-ज़ैग मार्ग प्रणाली शुरू की जाएगी, तथा भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस बलों की तैनाती बढ़ाई जाएगी। चंडी देवी मंदिर तक जाने वाले पैदल मार्गों की खराब स्थिति पर भी चिंता व्यक्त की गई। बैठक में शामिल महंत भवानी शंकर ने त्योहारों के दिनों में तत्काल पुलिस बल की उपस्थिति की आवश्यकता पर बल दिया और बिगड़ते बुनियादी ढाँचे की ओर ध्यान दिलाया अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि इन सड़कों की मरम्मत का काम शुरू किया जाएगा, साथ ही मार्ग पर तीर्थयात्रियों के लिए शौचालय और विश्राम स्थलों का निर्माण भी किया जाएगा। भीड़ नियंत्रण के अलावा, प्रशासन ने मंदिर परिसर में बिजली कनेक्शनों की ऑडिटिंग के आदेश दिए हैं।

सम्पादकीय

शतरंज के वैश्विक बोर्ड पर भारत का दिव्य अधिकार

वैश्विक शतरंज में वर्ष 2025 एक ऐसी दिव्य उपलब्धि लेकर आया है जिसे तब तक स्मरण किया जाएगा जब तक वैश्विक मंच पर शतरंज खेला जाएगा और शतरंज के प्रेमी रहेंगे। भारत की 88वीं ग्रैंड मास्टर बनीं 19 वर्षीय दिव्या देशमुख ने जार्जिया के बाटुमी में हुए फिडे महिला शतरंज विश्व कप प्रतियोगिता में अपने ही देश की कोनेरू हंपी को पराजित करते हुए इतिहास रच दिया। इसके साथ ही दिव्या शतरंज के खेल की नई सनसनी बन गई हैं। अभी तक दिव्या को 15वीं वरीयता प्राप्त थी किंतु दृढ़ता और ओपनिंग की तैयारियों ने दिव्या को चैंपियन बना दिया है। नागपुर की रहने वाली 19 वर्षीया दिव्या देशमुख भविष्य में कई युवाओं को उसी प्रकार से खेल के प्रति उत्साहित करने में सक्षम हो गई हैं जैसे कि भाला फेंक प्रतियोगिता में नीरज चोपड़ा कर रहे हैं। दिव्या के पिता डा. जितेंद्र और माता नम्रता देशमुख दोनों ही चिकित्सक हैं। दिव्या ने सबसे पहले 2012 में अंडर-सात में राष्ट्रीय शतरंज प्रतियोगिता जीतकर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई। दिव्या ने 214 में दक्षिण अफ्रीका के डरबन में अंडर 10 और 2017 में ब्राजील में अंडर-12 वर्ल्ड यूथ खिताब जीते। वह 2021 में विदर्भ क्षेत्र की पहली महिला ग्रैंड मास्टर बनीं। उन्होंने 2023 में इंटरनेशनल मास्टर की प्रतियोगिता जीती। फिर उन्होंने ग्रैंड मास्टर आर. बी. रमेश के मार्गदर्शन में चेन्नई के शतरंज गुरुकुल में अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। दिव्या शतरंज ओलम्पियाड में तीन बार की स्वर्ण पदक विजेता हैं। दिव्या ने एशियन चैम्पियनशिप और वर्ल्ड जूनियर चैम्पियनशिप में भी स्वर्णपदक जीता। दिव्या ने वर्ष 2024 में बुडापेस्ट में 45वें शतरंज ओलम्पियाड में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया और वर्ल्ड टीम रैपिड और ब्लिट्ज शतरंज प्रतियोगिता में भी शानदार प्रदर्शन किया। दिव्या की बड़ी बहन बैडमिंटन खेलने के लिए जाती थीं और उनके साथ दिव्या भी जाती थी किंतु उन्हें शतरंज में रूचि थी और वे उसी में रम गई आज वह शतरंज की सर्वोत्कृष्ट खिलाड़ी हैं। वर्ष 2025 में दिव्या ने चीन की 22 वर्षीय ग्रैंडमास्टर झू जिनर को हराकर शानदार जीत हासिल की, वहीं दूसरी भारतीय महिला खिलाड़ी कोनेरू हंपी ने भी चीनी खिलाड़ी को ही हराकर फिडे शतरंज विश्वकप में चीन का दबदबा ध्वस्त कर दिया है। यह भारत के लिए बड़ी अभूतपूर्व दोहरी सफलता रही है कि फिडे विश्व कप के फाइनल में दोनों ही खिलाड़ी भारतीय रहे। अब विश्व शतरंज में भारत की धमक बढ़ रही है और भारत के खिलाड़ी देश का ध्वज शतरंज के बोर्ड पर लहरा रहे हैं। इससे पूर्व पुरुष शतरंज में 18 वर्षीय डी. गुकेश ने चीन के डिंग लिरेन को हराकर कीर्तिमान रचा था। उनकी यह उपलब्धि सिर्फ व्यक्तिगत उपलब्धि ही नहीं थी अपितु भारतीय शतरंज की एक बड़ी छलांग थी। विगत वर्ष सितंबर माह में ही भारत ने बुडापेस्ट में हुए 45वें शतरंज ओलम्पियाड में भी शानदार प्रदर्शन किया था जिसमें महिला और पुरुष दोनों ही टीमों ने स्वर्ण पदक जीतकर देश को गर्व से भर दिया था। भारत के कई अन्य ग्रैंड मास्टर भी वैश्विक जगत में अपनी चमक बिखेर रहे हैं। जिसमें आर. प्रगनानंद, विदित गुजराती, अर्जुन ऐरिगिसी, आर वैशाली और डी. हरिका जैसे युवा खिलाड़ी प्रमुख हैं। आज पूरा भारत शतरंज की दुनिया में अपनी बेटियों की सफलता पर गर्व का अनुभव कर रहा है। भविष्य में यही युवा खिलाड़ी अन्य खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा का स्वर बनने जा रहे हैं। अब शतरंज के आकाश पर भारत का राज स्थापित हो रहा है। यह पल भारत के लिए बेहद गर्व के पल हैं।

जयंती

प्रेमचंद

जन्म: 31 जुलाई, 1880–मृत्यु: 8 अक्टूबर, 1936) भारत के उपन्यास सम्राट माने जाते हैं जिनके युग का विस्तार सन् 1880 से 1936 तक है। यह कालखण्ड भारत के इतिहास में बहुत महत्त्व का है। इस युग में भारत का स्वतंत्रता-संग्राम नई मंज़िलों से गुजरा। प्रेमचंद का वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। वे एक सफल लेखक, देशभक्त नागरिक, कुशल वक्ता, ज़िम्मेदार संपादक और संवेदनशील रचनाकार थे। बीसवीं शती के पूर्वार्द्ध में जब हिन्दी में काम करने की तकनीकी सुविधाएँ नहीं थीं फिर भी इतना काम करने वाला लेखक उनके सिवा कोई दूसरा नहीं हुआ।

पुण्यतिथि

आर. डी. प्रधान

जन्म-27 जून, 1928; मृत्यु-31 जुलाई, 2020) पूर्व केंद्रीय गृह सचिव थे। राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे, तब आर. डी. प्रधान डेढ़ वर्ष तक केंद्रीय गृह सचिव रहे थे। वे साल 1998 से 2003 तक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में सोनिया गांधी के कार्यालय के प्रभारी भी रहे। वह बिहार और फिर 19 मार्च, 1987 से 16 मार्च, 1990 तक अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल भी रहे।

कल मिलेंगे

गर्लफ्रेंड उदास होकर बैठी थी
बॉयफ्रेंड-तबीयत ठीक नहीं है क्या?
जाओ डॉक्टर को दिखा लो
गर्लफ्रेंड-दिखाया था यार डॉक्टर को
बॉयफ्रेंड-क्या बताया उसने?
गर्लफ्रेंड-बोल रहा था...खून में शॉपिंग की कमी है
बोला है थोड़ा मॉल घूमकर आओ
बॉयफ्रेंड बेहोश.

संजना भारती दैनिक

भगवान शंकर जी के 11वें रुद्रावतार हनुमान जी (मेंहदीपुर, श्री बाला जी) के संरक्षण में संचालित किया जाता है। समाचार पत्र का यह अंक भी उन्हीं के चरणों में श्रद्धापूर्वक समर्पित है।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक-**संजय कुमार** द्वारा आर.डी. प्रिंटर एंड पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड, ए-41, सेक्टर-8, नोएडा, उत्तर प्रदेश से मुद्रित तथा ए-281सी, गली नं. 3, ए-ब्लॉक, अम्बिका विहार, शिव विहार, दिल्ली-110094 से प्रकाशित। इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत संपादक उत्तरदायी।

RNI No. : DELHIN/2016/70240

Phone No.: 9871221635
E-mail ID: sanjanabharati16@gmail.com
(किसी भी वाद-विवाद में न्याय क्षेत्र दिल्ली ही होगा।)

जानें प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह और जयशंकर के संसद में दिये गये भाषणों का पूरा निचोड़

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने विपक्ष के इस आरोप को खारिज कर दिया कि अमेरिका या अन्य देशों के दबाव में भारत ने ऑपरेशन रोका। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच इस अवधि में कोई सीधा संवाद नहीं हुआ था। इसके अलावा, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री के संबोधनों से जो मुख्य बिंदु उभर कर आये उसके मुताबिक, संयुक्त राष्ट्र के 193 देशों में से केवल तीन ने पाकिस्तान का समर्थन किया

-नीरज कुमार दुबे

लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर हुई चर्चा ने यह स्पष्ट कर दिया कि मोदी सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी रणनीति और नीतियों में एक निर्णायक और आक्रामक दृष्टिकोण अपनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने अपने भाषणों में यह संदेश दिया कि भारत न केवल हमलों का त्वरित जवाब देने में सक्षम है, बल्कि हर बार नये मानक भी स्थापित करता है। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण की बात करें तो आपको बता दें कि उनका संबोधन इस बात का प्रमाण था कि अब आतंकवादियों के आकाओं को पता है कि भारत चुप नहीं बैठेगा। उन्होंने बताया कि 22 अप्रैल के पहलगाम हमले का बदला लेने के लिए भारत ने मात्र 22 मिनट में निर्धारित लक्ष्यों पर सटीक सैन्य प्रहार किया था। मोदी ने अपने संबोधन के माध्यम से तीन मुख्य संदेश दिए- 1. भारत अपनी शर्तों पर जवाब देगाः अब कोई परमाणु ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी।ह्व 2. इस ऑपरेशन में मेड इन इंडिया ड्रोन और मिसाइलों का सफल प्रयोग भारत की रक्षा स्वायत्तता का प्रतीक था। 3. उन्होंने बताया कि संयुक्त राष्ट्र के 193 देशों में से केवल तीन देशों ने पाकिस्तान के पक्ष में बयान दिया, जबकि बाकी देशों ने भारत का समर्थन किया। मोदी ने विपक्ष पर यह आरोप भी लगाया कि उसके नेता पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं और जवानों के पराक्रम को राजनीतिक चश्मे से देख रहे हैं। यह विपक्ष की नैतिक अस्थिरता को उजागर करता है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के संबोधन पर गौर करें तो आपको बता दें कि उन्होंने स्पष्ट किया कि पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड सुलेमान, अफगान और जिब्रान जैसे अ-श्रेणी के आतंकियों को ऑपरेशन महादेव में मारा गया। उन्होंने बताया कि यह अभियान भारतीय सेना, सीआरपीएफ और जम्मू-कश्मीर पुलिस के संयुक्त प्रयास का नतीजा था। अमित शाह ने कहा कि आतंकियों के खिलाफ सबूत इतने मजबूत थे कि उनके पाकिस्तानी मतदाता पहचान पत्र तक बरामद हुए। उन्होंने विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा कि यह कैसी राजनीति है कि आतंकियों के मारे जाने पर भी उनके चेहरे फीके पड़ गए। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने संबोधन में ऑपरेशन सिंदूर को तीनों सेनाओं के समन्वय का बेमिसाल उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन का मकसद किसी क्षेत्र पर कब्जा करना नहीं, बल्कि पाकिस्तान द्वारा पाले गए आतंकवाद की नर्सरी को खत्म करना था। राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि उसने दोबारा आतंकवादी गतिविधियां कीं तो ऑपरेशन सिंदूर को पुनः शुरू करने में देर नहीं लगेगी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि 10 मई की सुबह भारतीय वायुसेना के करारे हमलों के बाद ही पाकिस्तान ने संघर्ष विराम की पेशकश की थी।

उधर, विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने विपक्ष के इस आरोप को खारिज कर दिया कि अमेरिका या अन्य देशों के दबाव में भारत ने ऑपरेशन रोका। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच इस अवधि में कोई सीधा संवाद नहीं हुआ था। इसके अलावा, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री के संबोधनों से जो मुख्य बिंदु उभर कर आये उसके मुताबिक, संयुक्त राष्ट्र के 193 देशों में से केवल तीन ने पाकिस्तान का समर्थन किया। सिंधु जल संधि को स्थगित करना और अटारी सीमा बंद करना आतंकवाद पर भारत की सख्त नीति का संकेत था। साथ ही क्वाड, ब्रिक्स और यूएनएससी में भारत ने स्पष्ट कर दिया कि आतंकवाद और बातचीत साथ-साथ नहीं चल सकते।

देखा जाये तो मोदी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत 22 मिनट में जवाबी कार्रवाई कर यह दिखा दिया कि अब लंबी चचाओं का समय खत्म हो चुका है। मेड इन इंडिया हथियारों के प्रयोग ने पाकिस्तान की मिसाइल और ड्रोन तकनीक की पोल खोल दी। साथ ही विदेश मंत्री जयशंकर के नेतृत्व में भारत ने विश्व स्तर पर यह विमर्श बनाया कि पाकिस्तान का आतंकवाद पूरी मानवता के लिए खतरा है। इसके अलावा, आतंकवादियों और उनके समर्थक देशों को अब यह समझना होगा कि भारत न केवल हमले का जवाब देगा बल्कि हमलावरों को समाप्त कर देगा। देखा जाये तो ऑपरेशन सिंदूर ने यह सिद्ध कर दिया कि भारत अब प्रतिरक्षात्मक नहीं, बल्कि प्रहारक रणनीति अपनाने वाला राष्ट्र है। आतंकियों को यह संदेश मिला कि उनके आकाओं को भी सुरक्षित ठिकाने नहीं मिलेंगे। मोदी सरकार ने न केवल पाकिस्तान की सैन्य और आतंकवादी क्षमता को करारा झटका दिया है बल्कि वैश्विक मंच पर यह स्थापित कर दिया है कि भारत किसी भी बाहरी दबाव में नहीं झुकेगा। यह नया भारत आत्मनिर्भर है, निर्णायक है और अपनी जनता के हितों की रक्षा करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है।

बहरहाल, संसद में दिये गये ये भाषण भारत की रक्षा नीति, आतंकी हमले का जवाब देने की नीति और विदेश नीति के परिदृश्य को दृढ़ता से प्रस्तुत करते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि मोदी सरकार ने आतंकवाद के विरुद्ध राष्ट्रीय आवाज बुलंद की है, हालांकि विपक्ष द्वारा सुरक्षा चौकसी और खुफिया विफलता पर की गई आलोचना भी ध्यान देने योग्य है। यह बहस एक समृद्ध तथ्यों और तर्कों की लड़ाई थी, जिसमें सरकार ने सफलता हासिल की, जबकि विपक्ष ने जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में प्रयास किया।

'ऑपरेशन सिंदूर' पर संसद में उठे सुलगते सवालों के मिले अस्पष्ट जवाबों के गम्भीर वैश्विक मायने को ऐसे समझिए

भारत और पाकिस्तान के बीच हुए 'संघर्ष विराम' की पहली जानकारी यदि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दी थी, तो आखिर कैसे, यह देशवासी जानना चाहते हैं। क्योंकि ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम की घोषणा करते हुए दावा किया था कि 'रात भर चली बातचीत' में अमेरिका ने मध्यस्थता की। ट्रेड की शर्तों पर युद्ध विराम करवाया

-कमलेश पांडेय

पहलगाम आतंकी हमले के बाद हुए ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े सुलगते हुए सवालों पर भारत की संसद के दोनों सदनों यानी राज्यसभा और लोकसभा में लगभग 32 घण्टे तक पक्ष और विपक्ष के बीच जोरदार बहस चली, लेकिन नेता प्रतिपक्ष के दहकते हुए कुछ सवालों का सटीक जवाब प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और गृहमंत्री आदि नहीं दे पाए! इसके पीछे मौलिक वजह यह बताई जाती है कि विपक्ष के कुछ मूर्खतापूर्ण सवालों का जवाब चतुर सत्तापक्ष ने रणनीतिक पूर्वक गोलमोल तरीके से दिया है। तभी तो यह सवाल उठने लगे कि पीएम मोदी के भाषण द्वारा मिले जवाब में कुछेक विपक्षी सवालों का सीधा और माकूल जवाब नहीं मिल पाया है?

इस बाबत राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पीएम मोदी भले ही संसद में अपनी बात रख चुके हों, लेकिन अभी तक उनके मार्फत कई सवालों के जवाब नहीं मिले हैं। कहा जा रहा है कि पीएम मोदी की स्पीच में बहुत सारे सवालों के जवाब तो मिले लेकिन ढेर सारे सवालों के जवाब, जवाब के तौर पर नहीं बल्कि सवाल के रूप में मिले। उदाहरण के तौर पर, सरकार ने इस बात का कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया कि आखिरकार सीजफायर क्यों किया गया? इसकी जानकारी घोषणा होने से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप तक कैसे पहुंच गई, जिन्होंने इस मसले पर सबसे पहले ट्वीट किया था? वहीं, पहलगाम से पुलवामा तक सुरक्षा मामलों में हुई चूक को लेकर किसी की तरफ से स्पष्ट जवाब नहीं मिला- चाहे वो रक्षा मंत्री हों, गृह मंत्री हों या प्रधानमंत्री!

उल्लेखनीय है कि भारत और पाकिस्तान के बीच हुए 'संघर्ष विराम' की पहली जानकारी यदि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दी थी, तो आखिर कैसे, यह देशवासी जानना चाहते हैं। क्योंकि ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम की घोषणा करते हुए दावा किया था कि 'रात भर चली बातचीत' में अमेरिका ने मध्यस्थता की। ट्रेड की शर्तों पर युद्ध विराम करवाया। वहीं, तब से अब तक राष्ट्रपति ट्रंप दो दर्जन से अधिक बार भारत-पाकिस्तान के बीच सीजफायर करवाने का दावा कर चुके हैं, जिससे भारत सरकार की कूटनीतिक सफलता पर सवाल उठना लाजिमी है।

दरअसल, गत सोमवार को भी स्कॉटलैंड में ब्रिटिश प्रधानमंत्री किएर स्टार्मर के साथ हुई बातचीत से पहले मीडिया को संबोधित करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान सहित दुनिया भर में चल रहे छह बड़े युद्ध को रोकने में अपनी भूमिका की बात कही थी। क्योंकि अंतरराष्ट्रीय शांति का नोबल पुरस्कार पाने के लिए वह लालायित हैं। वहीं भारतीय विपक्ष ने निरंतर यह सवाल उठाया कि मोदी सरकार ने इस पर चुप्पी क्यों साधी है? क्या यह दावा सच है या झूठ? मोदी ने अपने संसदीय बयान में भी ट्रंफ का ज़िक्र क्यों नहीं किया?

इसका सीधा जवाब यही होगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी स्पीच में न तो अमेरिका का नाम लिया और न ही डोनाल्ड ट्रंप का ज़िक्र किया। क्योंकि वैश्विक कूटनीति में ऐसा नहीं होता कि किसी नेता का नाम लेकर सरकार बयान दे। जहां तक अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की बात है तो वह दुनिया के सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति हैं। वहीं, इस पूरी बहस में सरकार ने चीन का नाम भी नहीं लिया है, जिसने पाकिस्तान की तरफ से पूरा युद्ध लड़ा है। इसलिए पूरक सवाल है कि जब चीन पर नहीं बोल रहे, तो ट्रंप पर कैसे बोलेंगे?

हां, इतना जरूर है कि तीसरे देश के हस्तक्षेप पर बोलते हुए पीएम मोदी ने दो कहा है कि, "दुनिया के किसी भी नेता ने भारत को ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। 9 तारीख (मई) की रात को अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझसे बात करने का प्रयास किया। वे घंटे भर कोशिश कर रहे थे, लेकिन उस समय सेना के साथ मेरी मीटिंग चल रही थी। मैं उनका फोन उठा नहीं पाया और बाद में जब उन्हें कॉल बैक किया। तो उन्होंने मुझसे कहा कि पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने वाला है। इस पर मेरा उन्हें जवाब था कि अगर पाकिस्तान का ये इरादा है, तो उसे बहुत महंगा पड़ेगा।"

इसलिए सवाल दर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर केंद्र की मोदी सरकार डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेने से क्यों बच रही है? तो इसका स्पष्ट जवाब यही होगा कि मौजूदा दौर में तेजी से आगे बढ़ रहा भारत अंतरराष्ट्रीय मोर्चा (इंटरनेशनल फ्रंट) पर विभिन्न प्रकार की कई चुनौतियों से जूझ रहा है। चूंकि बहुत सारी चीजें बातचीत की मेज पर हैं, इसलिए ट्रंप जैसे व्यक्ति का नाम लेकर भारत अपना पक्ष कमजोर नहीं करना चाहता है। लेकिन इसका मतलब यह भी कतई नहीं है कि सरकार ट्रंप को सही ठहरा रही है। बस भारत अनावश्यक रूप से और अधिक समस्याएं खड़ा नहीं करना चाहता है। इसलिए भारत अपनी रणनीति में सफल है, जबकि विदेशी एजेंडे पर सियासी गोले बरसा रहा विपक्ष बेचैन!

भारत का विपक्ष एक और सवाल जानना चाहता है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत के कितने फाइटर जेट गिरे? हालांकि, उसे यह भी पूछना चाहिए था कि पाकिस्तान के कितने फाइटर जेट मार गिराए गए। इसका दो टूक जवाब यह होगा कि सर्वप्रथम भारतीय सेना ने रफाल लड़ाकू विमान गिराने के दावे को खारिज किया था। लेकिन उसके ही एक वरिष्ठ अधिकारी ने विदेश में यह बात कबूल ली की ऐसा कुछ हुआ है। यह विरोधाभाषी स्थिति ही मोदी सरकार के गले की हड्डी बन चुकी है। इससे उत्साहित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसी महीने दावा किया था कि मई में भारत-पाकिस्तान के बीच चले संघर्ष के दौरान 'पांच लड़ाकू विमान मार गिराए गए थे। हालांकि, ट्रंप ने यह स्पष्ट नहीं किया कि किस देश के कितने विमान गिराए गए। इससे पहले पाकिस्तान भी भारत के 'पांच लड़ाकू विमान मार गिराने' का दावा कर चुका है, जिसे भारत ने हमेशा खारिज किया है।

उल्लेखनीय है कि कांग्रेस इससे पहले भी केंद्र सरकार से यह स्पष्ट करने की मांग कर चुकी है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के कितने जेट गिरे थे। हालांकि, प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र सरकार ने अब तक इस सवाल का कोई सीधा जवाब नहीं दिया है। जबकि लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस विषय पर जवाब देते हुए सेना की सराहना की और कहा, "कुछ विपक्षी सदस्य पूछ रहे हैं कि कितने एयरक्राफ़्ट गिराए गए। मुझे लगता है कि यह सवाल हमारी राष्ट्रीय भावना के अनुरूप नहीं है। क्योंकि इन्होंने यह नहीं पूछा कि दुश्मनों के कितने एयरक्राफ़्ट गिराए गए।" भारतीय प्रतिपक्ष सरकार से यह भी जानना चाहता है कि भारत की तुलना में पाकिस्तान के साथ ज्यादा देश क्यों हैं? क्योंकि भारत-पाकिस्तान संघर्ष के दौरान तुर्की, अजरबैजान और चीन ने खुले तौर पर पाकिस्तान का समर्थन किया था। जबकि भारत के पक्ष में केवल इसराइल स्पष्ट रूप से खड़ा नजर आया। यहां तक कि रूस ने भी भारत का खुलकर समर्थन नहीं किया था। इस मुद्दे पर बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि, "दुनिया में किसी भी देश ने भारत को अपनी सुरक्षा में कार्रवाई करने से रोका नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में 193 देश हैं और सिर्फ तीन देशों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के समर्थन में बयान दिया था। क्वाड, ब्रिक्स, फ्रांस, रूस और जर्मनी...कोई भी देश का नाम ले लीजिए, दुनिया भर से भारत को समर्थन मिला।" इस बारे में मेरी स्पष्ट राय यह है कि जब भारत यूक्रेन के खिलाफ रूस का खुला साथ नहीं देगा तो क्यों रूस से यह उम्मीद की जाए कि वह पाकिस्तान के खिलाफ भारत का साथ पहले की तरह खुलकर देगा! कुछ यही बातें अन्य देशों पर भी लागू होती हैं। इस मामले में इजरायल अपवाद है, क्योंकि वह भी भारत की तरह ही इस्लामिक कट्टरता से जूझ रहा है। इसलिए भारत का उसने बिना किसी शर्त के साथ सहयोग किया है।

वहीं, इससे जुड़ा सवाल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गत सोमवार को संसद में उठाया और कहा कि, "विदेश मंत्री ने अपने भाषण में कहा था कि सभी देशों ने आतंकवाद की निंदा की है, यह बिल्कुल सही है। लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि पहलगाम हमले के बाद किसी एक भी देश ने पाकिस्तान की निंदा नहीं की। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि दुनिया हमें पाकिस्तान के साथ रख रही है।" उन्होंने जोर देते हुए आगे कहा कि, "जब यूपीए सरकार थी, तब दुनिया के अलग-अलग देश पाकिस्तान की आतंकवाद के लिए आलोचना करते थे। जो व्यक्ति पहलगाम हमले के पीछे था- जनरल मुनीर, वह राष्ट्रपति ट्रंप के साथ लंच कर रहा है। हमारे प्रधानमंत्री वहां नहीं जा सकते, लेकिन जनरल मुनीर लंच कर रहा है।"

इस बारे में सिर्फ इतना ही कहना समीचीन होगा कि हर देश अपने हितों को ध्यान में रखते हुए ही भारत का समर्थन करेगा, क्योंकि उन्हें भी वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में सोचना है। कई देशों ने भारत की निंदा नहीं की है। इसे भारत के समर्थन के रूप में ही देखना चाहिए. यह बहुत बड़ी बात है। सवाल है कि आखिर पाकिस्तान के साथ भारत क्रिकेट क्यों खेल रहा है? क्या यह उचित है? जवाब होगा- बिल्कुल नहीं। इसे अविलंब रोक देना चाहिए। बता दें कि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने ऑपरेशन सिंदूर' पर संसद में विशेष चर्चा के दौरान सवाल उठाया कि जब पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सख़्त रुख अपनाया था, तो अब 14 सितंबर को क्रिकेट के एशिया कप में भारत की टीम पाकिस्तान के खिलाफ कैसे खेलेगी?

ओवैसी ने कहा, "पाकिस्तान से ट्रेड बंद है। वहां के प्लेन यहां नहीं आ सकते। जल क्षेत्र में जहाज नहीं आ सकता है। आपका जमीर ज़िंदा क्यों नहीं है? किस सूरत से आप पाकिस्तान से क्रिकेट खेलेंगे?" बता दें कि भारत-पाकिस्तान संबंधों में तनाव के बीच एशियन क्रिकेट काउंसिल (एसीसी) ने हाल ही में एशिया कप 2025 का शेड्यूल जारी किया है, जिसमें भारत और पाकिस्तान को एक ही ग्रुप में रखा गया है। दोनों टीमों के बीच पहला मुकाबला 14 सितंबर को तय है। अगर दोनों टीमें फाइनल तक पहुंचती हैं, तो दो और मैच भी हो सकते हैं।

ऐसे में सुलगता हुआ सवाल है कि जब हमने राजनयिक रिश्ते सस्पेंड कर दिए हैं, तो हम क्रिकेट मैच क्यों खेल रहे हैं? जब भारत कहता है कि ट्रेड और टेरर साथ नहीं चलेंगे, ट्रेड और टॉक साथ नहीं चलेगी, खून और पानी साथ नहीं चलेगा, तो फिर खेल और खून कैसे साथ साथ चलेंगे? सरकार को इसे स्पष्ट करना चाहिए। जबकि आरोप है कि सरकार की तरफ से इसका कोई ठोस जवाब क्यों नहीं दिया गया? स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत-पाकिस्तान संघर्ष के दौरान सीजफायर को लेकर मध्यस्थता' वाले दावे को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने संसद में 'ऑपरेशन सिंदूर' पर चल रही बहस के दौरान दिए गए भाषण में कहा कि भारत ने कभी किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता स्वीकार नहीं की और न अब करेगा। जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कई बार दोहरा चुके हैं कि उन्होंने 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान भारत-पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम में भूमिका निभाई थी।

(इस लेख में लेखक के अपने विचार हैं।)

खेल/विदेश/कारोबार/फिल्म

फ्रांस के बाद अब ब्रिटेन भी हुआ फिलिस्तीन के साथ

(एजेन्सी)।

डाउनिंग स्ट्रीट ने मंगलवार को घोषणा की कि यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने सितंबर में होने वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा से पहले एक फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने की प्रतिबद्धता जताई है। स्टारमर ने अपने मंत्रिमंडल की एक विशेष बैठक में कहा कि गाजा में बिगड़ती मानवीय स्थिति और शांति प्रक्रिया की घटती संभावनाओं को देखते हुए इस स्थिति को आगे बढ़ाने का यही सही समय है। पॉलिटिको की एक रिपोर्ट के अनुसार, इजराइल सरकार ने इस कदम को हमास के लिए इनाम बताकर तुरंत खारिज कर दिया, जबकि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इसे तुष्टिकरण बताया। ब्रिटेन का यह रुख गाजा में भुखमरी से मरते बच्चों की तस्वीरों से उपजे आक्रोश और ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर पर लेबर बार्टी के सांसदों के दबाव के चलते सामने आया है। बीएम स्टारमर ने कहा था कि यह कदम एक व्यापक डी-राष्ट्र समाधान के हिस्से के तौर पर ही लिया जाना चाहिए, जो इजराइल और फिलिस्तीन दोनों के लिए थायी शांति सनिधान करे।

अब ब्रिटेन के 9 दलों के 250 से अधिक सांसदों ने पीएम स्टारमर और विदेश मंत्री डेविड लैमी को पत्र लिखकर फिलिस्तीन को मान्यता देने की मांग की है। लेबर सरकार के कई मंत्री भी इसके पक्ष में हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की स्कॉटलैंड यात्रा के दौरान उनसे मुलाकात के बाद पीएम स्टारमर ने गाजा के मुद्दे पर ब्रिटिश संसद का आपातकालीन सत्र बुलाया है। ब्रिटेन पहले ही इजराइल के 2 कट्टरपंथी मंत्रियों पर प्रतिबंध लगा चुका है और यूएन राहत एजेंसी की फंडिंग बहाल कर चुका है। इन कूटनीतिक कदमों से साफ है कि ब्रिटेन अब गाजा संकट में एक संतुलित, लेकिन निर्णायक भूमिका निभाने की दिशा में बढ़ रहा है। आपको बता दें कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने घोषणा की कि उनका देश फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता देगा। इजरायल के हमले के कारण खाद्यान्न एवं आवश्यक सामग्री की आपूर्ति के संकट से जूझ रहे गाजा में मौजूदा हालात को लेकर दुनिया भर के देशों में व्याप्त आक्रोश के बीच फ्रांस के इस फैसले को साहसिक कूटनीतिक कदम माना जा रहा है। मैक्रों ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा में इस फैसले को औपचारिक रूप देंगे। उन्होंने कहा कि आज सबसे जरूरी बात यह है कि गाजा में युद्ध रुके और आम नागरिकों की जान बचे।

सोने में उछाल, चांदी लुढ़की

(एजेन्सी)।

सोने की कीमतों में तेजी जारी रही। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर सोने का 5 अगस्त का अनुबंध 239 रुपये की बढ़त के साथ 98,500 रुपये प्रति 10 ग्राम पर खुला, जबकि पिछला बंद भाव 98,261 रुपये था। यह आगे बढ़कर 99,380 रुपये के उच्चतम स्तर पर पहुँच गया। पिछली बार यह 191 रुपये या 0.19 प्रतिशत की बढ़त के साथ 99,310 रुपये पर कारोबार कर रहा था। बीच में इसने 99,122 रुपये का निचला स्तर भी छुआ था। दूसरी ओर, 5 सितंबर, 2025 को चांदी वायदा ने सत्र की शुरूआत लाल निशान में की। एमसीएक्स पर यह अनुबंध 89 रुपये की गिरावट के साथ 1,13,664 रुपये प्रति किलोग्राम पर खुला, जबकि पिछला बंद भाव 1,13,753 रुपये था। यह और गिरकर 1,13,467 रुपये के निचले स्तर को छू गया। अंतिम बार यह 1,13,600 रुपये पर कारोबार कर रहा था -पिछले बंद भाव से 153 रुपये या 0.13 प्रतिशत की गिरावट। बीच में, इसने 1,14,023 रुपये का उच्च स्तर भी छुआ। मजबूत हाजिर मांग के बीच सटोरियों के ताजा सौदों से वायदा कारोबार में सोने का भाव बुधवार को 150 रुपये चढ़कर 99,380 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) में अगस्त में आपूर्ति वाले सोने की कीमत 150 रुपये यानी 0.15 प्रतिशत बढ़कर 99,380 प्रति 10 ग्राम हो गई। इसमें 12,181 लॉट के लिए कारोबार हुआ। विश्लेषकों ने बताया कि प्रतिभागियों के ताजा सौदे करने से सोने के कीमतों में तेजी आई है। वैश्विक स्तर पर न्यूयॉर्क में सोना का वायदा भाव 0.01 प्रतिशत की बढ़त के साथ 3,327.08 डॉलर प्रति औंस रहा। कारोबारियों के सौदों का आकार कम करने से वायदा कारोबार में चांदी की कीमत बुधवार को 28 रुपये की गिरावट के साथ 1,13,467 रुपये प्रति किलोग्राम रह गई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) में चांदी के सितंबर महीने में आपूर्ति वाले अनुबंधों की कीमत 28 रुपये यानी 0.02 प्रतिशत की गिरावट के साथ 1,13,467 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई। इसमें 15,622 लॉट का कारोबार हुआ।

धड़क 2 का ट्रेलर निर्माताओं द्वारा जारी

(एजेन्सी)।

लंबे समय से अटकी हुई धड़क 2 का ट्रेलर शुक्रवार को निर्माताओं द्वारा जारी कर दिया गया। यह फिल्म कुछ समय से केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) के पास अटकी हुई थी और जाति के मुद्दे पर आधारित होने के कारण इसमें कुछ कट्स भी लगाने पड़े। यह मारी सेल्वराज द्वारा निर्देशित और पा रंजीत द्वारा निर्मित, दमदार तमिल फिल्म, परियेरुम पेरुमल (2018) का रीमेक है।

परियेरुम पेरुमल में परियन (कथिर) की कहानी है, जो एक उत्पीड़ित जाति से ताल्लुक रखता है और बीआर अंबेडकर जैसा वकील बनने के लिए एक लॉ कॉलेज में दाखिला लेता है। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान, उसकी दोस्ती ज्योति महालक्ष्मी (आनंदी) से होती है, जो एक उच्च जाति से ताल्लुक रखती है और उसे अंग्रेजी पढ़ाती है। उनका बढ़ता रिश्ता अंततः दोनों के लिए एक बाधा बन जाता है क्योंकि उसका परिवार परियन को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर देता है क्योंकि वह एक उत्पीड़ित जाति से ताल्लुक रखता है। त्रिप्ति डिमरी और सिद्धांत चतुर्वेदी दो दिनों में आने वाली फिल्म धड़क 2 में नजर आएंगे। धर्मा प्रोडक्शंस द्वारा निर्मित इस फिल्म का निर्देशन शाजिया इकबाल ने किया है। यह दो अलग-अलग जातियों के व्यक्तियों की प्रेम कहानी पर आधारित है। अपने प्यार को पाने के लिए उन्हें जिन कठिनाइयों और संघर्षों से गुजरना पड़ता है, वही फिल्म का मुख्य कथानक है। निर्माताओं ने फिल्म के गानों और ट्रेलर के साथ दर्शकों में इतनी उत्सुकता पैदा कर दी है कि ऐसा लग रहा है कि धड़क 2, अहान पांडे और अनीत पड्डा की फिल्म सैयारा को टक्कर दे सकती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि धड़क 2 एक तमिल फिल्म का हिंदी रीमेक है जिसे आलोचकों की प्रशंसा मिली थी और जिसने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया था? जी हाँ! त्रिप्ति और सिद्धार्थ की यह फिल्म परियेरुम पेरुमल बी.ए.बी.एल. पर आधारित है। 2018 में रिलीज हुई इस फिल्म में कथिर और आनंदी मुख्य भूमिकाओं में हैं। फिल्म का निर्देशन मारी सेल्वराज ने किया था। अगर आप धड़क 2 से पहले ओरिजिनल फिल्म देखना चाहते हैं, तो आप इसे ओटीटी पर देख सकते हैं। 2018 में इंटरनेट पर लोगों और आलोचकों को प्रभावित करने वाली परियेरुम पेरुमल अमेजन प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है। हालाँकि, यह फिल्म केवल तमिल में ही उपलब्ध है।

एक बार फिर भारत ने पाकिस्तान के साथ मैच खेलने से किया इनकार

(एजेन्सी)। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स के सेमीफाइनल में भारत चैंपियंस ने पाकिस्तान चैंपियंस के खिलाफ खेलने से एक बार फिर इनकार कर दिय है। ये मैच गुरुवार 31 जुलाई को होना था। भारतीय टीम का कहना है कि वे पाकिस्तान के खिलाप किसी भी तरह का मुकाबला नहीं खेलना चाहते। टीम ने पहलगाम में हुए भीषड़ आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान के साथ किसी भी द्विपक्षीय खेल संबंध के खिलाफ देश के रुख का हवाला दिया है। भारत चैंपियंस ने मंगलवार को वेस्टइंडीज चैंपियंस को सिर्फ 13.2 ओवर में हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ मैच को लेकर उन्होंने पहले ही आपत्ति जताई थी। इससे पहले भी ग्रुप स्टेज का भारत-पाकिस्तान मैच रद्द कर दिया गया था। क्योंकि खिलाड़ियों और टूर्नामेंट के एक मुख्य स्पॉन्सर ने विरोध जताया था। वहीं गुरुवार को भारत ने एजबेस्टन क्रिकेट ग्राउंड पर टूर्नामेंट का सेमीफाइनल में पाकिस्तान से खेलना था। EasMyTrip नाम की कंपनी, जो टूर्नामेंट की स्पॉन्सर थी, ने भी सेमीफाइनल मैच से खुद को अलग कर लिया। कंपनी के सह-संस्थापक निशांत पिट्टी ने कहा कि भारत के लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए हम इस मैच से पीछे हट रहे हैं। उनके अनुसार, आतंकवाद और क्रिकेट एक साथ नहीं चल सकते।

भारतीय पहलवान हरदीप ने एशेंस में रचा इतिहास

(एजेन्सी)। अंडर-17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत के हरदीप ने 11 किलोग्राम ग्रीको रोमन वर्ग में गोल्ड पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया। फाइनल मुकाबले में हरदीप ने ईरान के यजदान रजा डेलरूज को कड़े मुकाबले में क्लाइटेरिया के आधार पर हराया, क्योंकि मैच 3-3 की बराबरी पर खत्म हुआ था। हरदीप ने क्वालिफिकेशन राउंड में कजाखस्तान के बाकतुर सोवेतखान को 2-0 से हराया। राउंड ऑफ 16 में उन्होंने पोलैंड के माटेउस यारोस्लाव टोमेल्का को 4-2 से मात दी। इसके बाद क्वार्टरफाइनल में यूक्रेन के अनातोली नोवाचेंको को 9-0 से पराजित किया। हरदीप ने क्वालिफिकेशन राउंड में कजाखिस्तान के बाकतुर सोवेतखान को 2-0 से हराया। राउंड ऑफ 16 में उन्होंने पोलैंड के माटेउस योरास्लाव टोमेल्का को 4-2 से मात दी। इसके बाद क्वार्टरफाइनल में यूक्रेन के अनातोली नोवाचेंको को 9-0 से पराजित किया। सेमीफाइनल में हरदीप ने तुर्किए के एमरूल्लाह कापकान को 4-2 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया और अंततः ऐतिहासिक गोल्ड पदक अपने नाम किया।

एक जैसे रासायनिक संयोजन वाली दवाइयों की कीमतों की सीमा तय की जाए: मीत हेयर

संजना भारती संवाददाता

चंडीगढ़/नई दिल्ली। संगरूर से आम आदमी पार्टी के लोकसभा सदस्य गुरमीत सिंह मीत हेयर ने संसद में शून्य काल के दौरान दवाइयों की अधिक कीमतों का मुद्दा उठाते हुए केंद्र सरकार से मांग की कि एक समान रासायनिक संरचना वाली दवाइयों की कीमतों की अधिकतम सीमा निर्धारित की जाए।

मीत हेयर ने शून्य काल में स्वास्थ्य से जुड़ा एक अहम विषय उठाते हुए कहा कि ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर (डी पी सी ओ), 2013 के तहत कुछ आवश्यक दवाओं की कीमतों पर नियंत्रण किया गया है, लेकिन जिन दवाइयों का उपयोग सबसे अधिक होता है, जैसे उच्च रक्तचाप और शुगर जैसी बीमारियों में दी जाने वाली दवाएं झ उन पर कीमत नियंत्रण लागू नहीं है। उन्होंने कहा कि इन बीमारियों के इलाज के लिए एक जैसे रसायनिक घटकों वाली दवाएं कई कंपनियों द्वारा बनाई जाती हैं, लेकिन उनकी कीमतें अलग-अलग होती हैं। यही कारण है कि एक ही दवा 3 रुपये में बनती है, लेकिन कोई कंपनी उसे 10 रुपये में, तो कोई 50 रुपये में बेच रही है। मीत हेयर ने कहा कि यह पूरे देश की एक साझी समस्या है, जहां दवाइयों की अत्यधिक कीमतों के चलते 300 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक का मुनाफा कमाया जा रहा है। उन्होंने सरकार से अपील की कि कम से कम एक समान रासायनिक संरचना वाली दवाइयों की अधिकतम कीमत तय की जाए, ताकि आम जनता को राहत मिल सके।

20 सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति की बैठक में योजनाओं पर हुई व्यापक चर्चा

एसबी ब्यूरो प्रमुख/मृगांक शेखर सिंह

जमुई। जमुई समाहरणालय स्थित संवाद कक्ष में 20-सूत्री जिला कार्यक्रम कार्यन्वयन समिति की बैठक मंत्री मध् निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग सह जिला प्रभारी मंत्री श्री रत्नेश सादा की अध्यक्षता में आयोजित की गई।

सर्वप्रथम जमुई के जिलाधिकारी श्री नवीन ने प्रभारी मंत्री सहित सभी आगत अतिथियों का स्वागत करते हुए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से बैठक की रूपरेखा प्रस्तुत की। इसके उपरांत प्रभारी मंत्री ने विभाग वार विभागीय कार्यों की समीक्षा किया। बैठक में उपस्थित विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों द्वारा उनके विभाग से संबंधित एवं संचालित योजनाओं की जानकारी प्रभारी मंत्री को दी गई। तदुपरांत अद्यतन प्रतिवेदन के आधार पर मंत्री द्वारा बिंदुवार समीक्षा की गई एवं कई बिंदुओं पर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में मुख्य रूप से स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, सिंचाई, पेयजल, बिजली, कृषि, खनन, मनरेगा, कल्याण, आपूर्ति, पथ निर्माण, समाज कल्याण समेत अन्य विभागों के पदाधिकारियों से संचालित योजनाओं की जानकारी ली गयी।

मुख्यतः आधार कार्ड अपडेट करने हेतु पंचायत स्तरीय कैंप लगाने, खनन मानक से अधिक की जांच, साफ स्वच्छ पेय जल, स्वास्थ्य, अम्बेडकर समग्र सेवा, जीविका, खनिज, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, आंगनवाड़ी, दाबील रोड जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई, इसके अतिरिक्त जनसंबंधी योजनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई। इस मौके पर जिला में श्रेष्ठ योगदान देने वाले पदाधिकारियों एवं कर्मियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।

इस बैठक में मुख्य रूप से जमुई की विधायक श्रेयसी सिंह, सिकंदरा के विधायक प्रफुल्ल कुमार मांझी, माननीय मंत्री के आप्त सचिव, जिलाधिकारी श्री नवीन, पुलिस कप्तान, अपर समाहर्ता, निदेशक डीआरडीए, 20 सूत्री के सभी प्रखंड अध्यक्ष, 20 सूत्री के सभी सदस्य, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, जिला कल्याण पदाधिकारी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम प्रबंधक, कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, कार्यपालक अभियंता, विद्युत प्रमंडल, श्रम अधीक्षक, जिला शिक्षा पदाधिकारी, सहायक निदेशक-सामाजिक सुरक्षा, जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक व अन्य संबंधित अधिकारी/कर्मी उपस्थित रहे।

पंजाब सरकार द्वारा नौवें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस संबंधी उच्च स्तरीय बैठक

1 करोड़ से ज्यदा संगत पहुंचेगी समागम में-हरजोत बैंस

एसबी संवाददाता

चंडीगढ़/श्री आनंदपुर साहिब। नौवें पातशाही, हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के अवसर पर पंजाब सरकार द्वारा चार धार्मिक यात्राएं और बड़े कार्यक्रम करवाने का फैसला लिया गया है। इन कार्यक्रमों की तैयारियों को लेकर आज विरासत-ए-खालसा में हुई पहली बैठक में पहुंचे पंजाब के कैबिनेट मंत्री स. हरजोत सिंह बैंस (विधायक, श्री आनंदपुर साहिब), कैबिनेट मंत्री स. हरभजन सिंह ई.टी.ओ. और कैबिनेट मंत्री स. तरुनप्रीत सिंह सौंद व पंजाब के पर्यटन एवं सांस्कृतिक मामलों के विभाग के सलाहकार दीपक बाली ने आयोजित किए जाने वाले धार्मिक कार्यक्रमों की रूपरेखा के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी।

उनके साथ पर्यटन विभाग के सलाहकार श्री दीपक बाली और पर्यटन विभाग के सचिव डॉ. अभिनव त्रिखा भी मौजूद थे। उन्होंने जिला प्रशासन और विभिन्न विभागों के अधिकारियों को सम्पूर्ण कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी दी और संगतों की सुविधा हेतु किए जाने वाले प्रबंधों को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए।

इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए स. हरजोत सिंह बैंस ने बताया कि 19 नवम्बर को मुख्यमंत्री पंजाब स. भगवंत सिंह मान की अगुवाई में श्रीनगर से श्री आनंदपुर साहिब के लिए चार दिवसीय धार्मिक यात्रा रवाना होगी और श्री आनंदपुर साहिब पहुंचने के उपरांत धार्मिक कार्यक्रमों के बाद यह यात्रा दिल्ली के लिए रवाना होगी। उन्होंने बताया कि इसी तरह गुरदासपुर से माझा-दोआबा यात्रा, मालवा से दो यात्राएं बठिंडा और फरीदकोट से श्री आनंदपुर साहिब के लिए रवाना होंगी जो प्रदेश के लगभग सभी जिलों और प्रमुख शहरों से होती हुई श्री आनंदपुर साहिब पहुंचेंगी। इन यात्राओं में मशाल-ए-शहादत, गुरु साहिब की जीवनी व शहादत से संबंधित पुस्तकालय, गतका, पंज निशानची, पंज प्यारे, कीर्तनी जत्थे, कश्मीरी पंडित और बड़ी संख्या में संगत सहित कश्मीरी प्रतिनिधि भी धार्मिक यात्रा में शामिल होंगे। श्री आनंदपुर साहिब में होने वाले धार्मिक कार्यक्रमों के बारे में हरजोत सिंह बैंस ने बताया कि विरासत-ए-खालसा में 23 नवम्बर को श्री अखंड पाठ साहिब की आरंभता होगी, जिसमें पंजाब के मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान समेत देश-विदेश की प्रमुख हस्तियाँ और धार्मिक व्यक्तित्व हाजिरी लगाएंगे। इसी दिन विरासत-ए-खालसा में मुख्यमंत्री पंजाब द्वारा श्री गुरु तेग बहादुर जी की अद्वितीय शहादत को दशार्ती डिजिटल प्रदर्शनी का उद्घाटन किया जाएगा। इंसानियत और मानव अधिकारों के रक्षक नौवें पातशाह के शहीदी कार्यक्रमों के अवसर पर सर्वधर्म सम्मेलन करवाए जाएंगे, जिनमें सिख इतिहास की जानकारी रखने वाले बुद्धिजीवी विचार-चर्चा करेंगे। उन्होंने बताया कि इसके उपरांत विरासत-ए-खालसा से एक गाइड टूर आयोजित किया जाएगा जो भाई जैता जी मेमोरियल और पंज प्यारा पार्क तक जाएगा, इस पार्क में कथा और कीर्तन दरबार सजाए जाएंगे।

उन्होंने बताया कि 24 नवम्बर को एक विशेष विधानसभा सत्र बुलाया जाएगा, इस पर भी विचार हो रहा है कि यह सत्र श्री आनंदपुर साहिब में बुलाया जाए। इस अवसर पर श्री आनंदपुर साहिब में हेरिटेज वॉक करवाई जाएगी, जिसमें श्री आनंदपुर साहिब के धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों के दर्शन कराए जाएंगे।

प्रभारी मंत्री स्वाभिमान संकुल संघ में जीविका दीदियों से किये संवाद

एसबी ब्यूरो प्रमुख/मृगांक शेखर सिंह

जमुई। जमुई के प्रभारी मंत्री रत्नेश सदा ने मंगलवार को सदर प्रखंड अंतर्गत खरगौर स्थित स्वाभिमान संकुल स्तरीय संघ पहुंचे, जहाँ पर वे महिला संवाद कार्यक्रम के तहत जीविका दीदियों से संवाद किये। इस अवसर पर उप विकास आयुक्त सुभाष चन्द्र मंडल, एसडीओ जमुई, जीविका के जिला परियोजना प्रबंधक श्री संजय कुमार, बीपीएम जमुई सदर स्वीटी कुमार, प्रशिक्षण अधिकारी अमरेंद्र कुमार, किरण कुमारी, सामुदायिक समन्वयक राहुल कुमार, राम प्रवेश कुमार मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन क्षेत्रीय समन्वयक दिनेश कुमार दास के द्वारा किया गया।

स्वभिमान संकुल संघ की अध्यक्ष बबिता पाण्डेय एवं सचिव सुनीता देवी ने मंत्री जी का स्वागत पुष्पगुच्छ देकर की। कार्यक्रम में जिला के प्रभारी मंत्री रतनेश सदा ने बिहार सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण की दिशा में क्रियान्वित महत्वाकांक्षी योजनाओं पर चर्चा किये। साथ ही उन्होंने महिला संवाद कार्यक्रम के दौरान आई आकाँक्षाओं पर भी चर्चा किये। उन्होंने बताया कि महिला संवाद कार्यक्रम के दौरान आई महत्वपूर्ण आकाँक्षाओं पर सरकार के द्वारा अमल किया गया, जिसमें पेंशन योजना में बढ़ोतरी, सभी पंचायतों में विवाह भवन, प्रखंड-सह-अंचल कार्यालय में साफ-सफाई का काम जीविका दीदियों को दिया गया। इससे न सिर्फ जीविका दीदियों को रोजगार मिला है, बल्कि आगे भी महिलाओं के उत्थान के लिए बिहार सरकार का प्रयास जारी रहेगा। उन्होंने कहा की जब हमारी महिलाएं सशक्त होंगी, तभी हमारा समाज आगे बढेगा। डीपीएम जीविका संजय कुमार ने जिले में जीविका के द्वारा की जा रही गतिविधियों से मंत्री जी को अवगत कराये। इस कार्यक्रम में पेंशन योजना की लाभार्थी निशा कुमारी और रेणुका देवी ने बताया पेंशन की राशि 400 से 11 सौ किये जाने पर हम सरकार का बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं। जमुई सदर प्रखंड परिसर में सफाई कर्मी के रूप में अभी हाल ही में नियुक्त की गई सरिता ने भी मंत्री के समक्ष अपनी बातों को रखते हुए कहा की आज उसे रोजगार मिला है, जिससे वह बहुत ही खुश हैं। वही शिवगुरु जीविका की लखी देवी ने बताया की महिला संवाद कार्यकम के दौरान उन्होंने अपने गाँव में नल-जल की समस्या को प्रमुखता से उठाया थो आज उनके गाँव में नल-जल की व्यवस्था सही कर दी गई है। साथ ही लखी देवी ने विवाह भवन को जल्द-से-जल्द से बनाये जाने की बात मंत्री जी समक्ष रखी। सतत जीविकोपार्जन योजना की लाभार्थी बुधनी देवी ने अपनी सफलता की कहानी साझा की उन्होंने ने बताया की गरसंडा पंचायत में आज योजना का लाभ पाकर वह किराना दुकान, बकरी पालन के साथ-साथ ई-रिक्शा भी खरीद चुकी हैं।

पंजाब में भीख मांग रहे बच्चों की जिंदगी बदल रही है: डॉ. बलजीत कौर

एसबी संवाददाता

चंडीगढ़। भीख मांग रहे बच्चों की ज़िंदगी को सड़कों से सुरक्षित, शिक्षा और आत्मनिर्भर जीवन की ओर ले जाने के लिए पंजाब सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रोजेक्ट जीवनजोत 2.0 मुहिम ऐसे परिणाम दे रही है जो राज्य में हो रहे सामाजिक बदलाव को दर्शाते हैं। यह खुलासा सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने किया।

सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने जानकारी देते हुए बताया कि अब तक 245 विशेष छापेमारी अभियानों के दौरान 214 भीख मांग रहे बच्चों को बचाया गया, जिनमें से 106 बच्चों को उनके माता-पिता को सौंप दिया गया है। ये परिणाम राज्य सरकार की इस मुहिम के प्रति प्रतिबद्धता को दशार्ते हैं।

मंत्री ने बताया कि ताजा कार्रवाई के अंतर्गत राज्य के 16 ज़िलों में 16 विशेष छापे मारे गए, जिनमें से केवल 2 बच्चे ही भीख मांगते हुए पाए गए झ एक बरनाला और एक संगरूर ज़िले से। दस्तावेजी जांच के बाद इन बच्चों को उनके माता-पिता को सौंप दिया गया। यह दशार्ता है कि मुहिम उद्देश्य की ओर सफलतापूर्वक आगे बढ़ रही है।

डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि अब तक कुल 16 बच्चों की डी.एन.ए. टेस्टिंग हेतु पहचान हो चुकी है, जिनमें से 15 बच्चों के लिए दस्तावेजी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और 13 बच्चों के डी.एन.ए. परीक्षण हेतु नमूने लिए जा चुके हैं। इसके अलावा, अमृतसर और गुरदासपुर ज़िलों में 1-1 और बठिंडा में 2 अभिभावकों के विरुद्ध (कुल 4) एफ.आई.आर. दर्ज की गई हैं।

डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि यह केवल एक कार्रवाई नहीं, बल्कि राज्य के हर बच्चे को सुरक्षा और भविष्य देने की दिशा में उठाया गया एक ठोस कदम है। उन्होंने कहा कि यदि किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी बच्चे को भीख मांगने के लिए मजबूर किया गया, तो उसके विरुद्ध सख़्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने समाजसेवी संस्थाओं और जनता से अपील की कि वे भीख जैसी बुरी सामाजिक बुराई को समाप्त करने के लिए सरकार का साथ दें। उन्होंने कहा, हम यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी बच्चा भीख मांगने के लिए मजबूर न हो झ हर बच्चा सुरक्षित, शिक्षित और आत्मनिर्भर बने, यही हमारा संकल्प है।

आवश्यक सूचना

तेजी से बढते राष्ट्रीय हिंदी दैनिक समाचार पत्र, '**संजना भारती**' को चंडीगढ़, पंचकुला सहित पूरा हरियाणा, पंजाब में जिला स्तर, तहसील स्तर, खंड स्तर पर पत्रकार/कोर्सपोंडेट/ प्रतिनिधि, जिला प्रभारी की जरूरत है।

संपर्क करें: दैनिक संजना भारती, समाचार पत्र नई दिल्ली
वाटसेप नम्बर: 9871221635

मिशन उम्मीद के तहत पंजाब डब्ल्यू.एच.ओ. के समर्थन से गुणवत्तापूर्ण कैंसर देखभाल सेवाएं प्रदान करने में अग्रणी बनेगा

कैंसर का शीघ्र पता लगाना ही इसके प्रभावी उपचार की कुंजी: स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह

संजना भारती संवाददाता

चंडीगढ़। कैंसर के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल के तहत, पंजाब सरकार ने विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ), भारत के साथ तालमेल बिठाकर बठिंडा, एसएएस नगर (मोहाली) और गुरदासपुर जिलों में एक व्यापक और जन-केंद्रित कैंसर देखभाल पायलट परियोजना 'मिशन उम्मीद' शुरू की है। इस महत्वपूर्ण परियोजना का उद्घाटन पंजाब के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, डॉ. बलबीर सिंह और भारत में डब्ल्यूएचओ के प्रतिनिधि डॉ. रोडेरिको एच. ओफ्रिन द्वारा संयुक्त रूप से किया गया, जो कैंसर देखभाल सेवाओं को मजबूत करने और सभी के लिए तत्काल, समान और गुणवत्तापूर्ण उपचार सुनिश्चित करने के लिए राज्य की प्रतिबद्धता के तहत एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

यह अग्रणी पहल विकेन्द्रीकृत और प्रणाली-आधारित दृष्टिकोण के माध्यम से मुंह, स्तन और गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर, जो भारत में तीन सबसे अधिक प्रचलित और रोकथाम योग्य कैंसर बीमारियाँ हैं, का शुरूआती चरण में ही पता लगाने, समय पर जांच और तुरंत उपचार सुनिश्चित करने के लिए तैयार की गई है। यह प्रणाली गैर-संचारी बीमारियों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपी-एनसीडी) के साथ रणनीतिक रूप से मेल खाती है और इसका उद्देश्य पंजाब की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के सभी स्तरों, अर्थात जमीनी स्तर पर आयुष्मान आरोग्य केंद्रों से लेकर उन्नत तृतीयक देखभाल अस्पतालों तक, कैंसर देखभाल सेवाओं को सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि इस साझेदारी का उद्देश्य कैंसर के मामलों संबंधी मौजूदा प्रवृत्ति को पलटना है, जहाँ पंजाब में 60 प्रतिशत से अधिक कैंसर के मामलों का पता उन्नत चरण में होता है, जिससे इसके प्रभावी ढंग से उपचार की गुंजाइश सीमित रह जाती है।

सभा को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि कैंसर का मतलब मृत्यु नहीं है और यदि समय पर इसका पता लग जाए तो यह बहुत हद तक ठीक हो सकता है। उन्होंने कहा कि इसका शीघ्र पता लगना ही इसके प्रभावी उपचार की कुंजी है। उन्होंने कहा कि यह पहल स्वास्थ्य में हमारे विश्वास को एक मौलिक अधिकार के रूप में दशार्ती है और सभी के लिए एक प्रभावी और समावेशी स्वास्थ्य प्रणाली बनाने के हमारे संकल्प का प्रतिबिंब है। उन्होंने कहा कि हम एक मिसाल कायम कर रहे हैं और यह दिखा रहे हैं कि कैसे आधुनिक स्वास्थ्य प्रणाली और मजबूत साझेदारी के माध्यम से हम मरीजों की कीमती जिंदगियां बचा सकते हैं। उन्होंने गैर-स्वस्थ जीवन शैली और खराब आहार संबंधी आदतों को कैंसर की बढ़ती घटनाओं के लिए एक बड़ा कारक बताया और नागरिकों को एक स्वस्थ दिनचर्या अपनाने की सलाह दी जिसमें रोजाना कम से कम एक घंटा शारीरिक कसरत और घर में पकाया पौष्टिक भोजन खाना आदि शामिल है। भारत में डब्ल्यू.एच.ओ. के प्रतिनिधि डॉ. रोडेरिको एच. ओफ्रिन ने पंजाब के सुचारु सार्वजनिक स्वास्थ्य दृष्टिकोण और एनएसडी (गैर-संचारी रोगों) की रोकथाम और नियंत्रण के लिए किए गए प्रयासों की सराहना की। उन्होंने आगे कहा कि 'मिशन उम्मीद' अपनी व्यापक कार्य योजना के साथ देश में व्यापक कैंसर देखभाल में अग्रणी भूमिका के रूप में उभरता है। उन्होंने कहा कि इन निवेशों और प्रयासों को कायम रखते हुए पंजाब 2030 तक एसडीजी-3 के एनएसडी लक्ष्यों को प्राप्त करने के रास्ते पर है। उन्होंने आगे कहा कि डब्ल्यू.एच.ओ. इस महत्वपूर्ण पहल में भागीदार होने पर गर्व महसूस करता है और इस मॉडल को देश भर में अपनाए जाने के लिए अपनी समग्र तकनीकी सहायता की पेशकश जारी रखेगा। कैंसर केयर पायलट एक तीन-स्तरीय मजबूत रेफरल मॉडल को अपनाता है और इसमें एक व्यापक श्रेणियां जैसे 30 वर्ष और इससे अधिक उम्र के व्यक्तियों की यूनिवर्सल स्क्रीनिंग से लेकर फ्रंटलाइन कार्यकताओं और क्लिनिकल स्टाफ की क्षमता में वृद्धि, फॉलो-अप और रेफरल प्रणालियों का एकीकरण, एनपी-एनसीडी पोर्टल के माध्यम से डिजिटल निगरानी, आशा, कम्युनिटी हेल्थ अधिकारियों और स्थानीय शासन ढाँचों के नेतृत्व में समुदायों की भागीदारी और जागरूकता अभियान शामिल हैं। यह परियोजना इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव जैसे क्षेत्रों में डब्ल्यू.एच.ओ. इंडिया के साथ पंजाब के मजबूत सहयोग पर आधारित है और अब कैंसर जैसी गंभीर चुनौती को हल करने के लिए उस साझेदारी का विस्तार करता है। शुरूआती खोज और उपचार के पालन में वृद्धि करने के अलावा, इस पायलट परियोजना का उद्देश्य तीसरे दर्जे के अस्पतालों पर बोझ घटाना, कम्युनिटी-स्तरीय स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करना और एक स्केलेबल मॉडल स्थापित करना है जो कैंसर की रोकथाम और उपचार में राष्ट्रीय और विश्वव्यापी रणनीतियाँ तैयार करता है।

इससे पहले डॉ. बलबीर सिंह ने स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस (एसटीजीज) भी जारी किए, जो स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं और नीति निमार्ताओं के लिए राज्य भर में समान, उच्च-गुणवत्ता वाली कैंसर देखभाल प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण रोडमैप प्रदान करते हैं। एसटीजीज एम्स दिल्ली, पीजीआई, होमी भाभा, सरकारी मेडिकल कॉलेजों के तकनीकी विशेषज्ञों और राज्य भर के विशेषज्ञों द्वारा तैयार किए गए हैं।

इस मौके पर प्रमुख सचिव स्वास्थ्य कुमार राहुल, विशेष सचिव स्वास्थ्य-सह-एमडी एनएचएम घनश्याम थोरी, निदेशक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण डॉ. हितिंदर कौर, एसपीओ एनपी-एनसीडी डॉ. गगनदीप सिंह ग्रोवर, प्रोग्राम ऑफिसर डॉ. आशु, डॉ. अभिषेक कुंवर नेशनल प्रोफेशनल ऑफिसर (एनसीडी) डब्ल्यूएचओ-भारत, डॉ. आशीष भट्ट नेशनल एनसीडी ऑफिसर डब्ल्यूएचओ -भारत, डॉ. अभिषेक खन्ना नेशनल प्रोफेशनल ऑफिसर (स्वास्थ्य प्रमोशन और एसडीएच) डब्ल्यूएचओ-भारत भी मौजूद थे।

अवैध कॉलोनियों को न पनपने दिया जाए: एडीसी सोनू भट्ट

जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक में अधिकारियों को दिए निर्देश

एसबी विशेष संवाददाता

करनाल। लघु सचिवालय स्थित सभागार में आयोजित जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक की अध्यक्षता करते हुए एडीसी सोनू भट्ट ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिले में किसी भी हालत में अवैध कॉलोनियों को पनपने न दिया जाए। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जो लोग बार-बार समझाने के बावजूद अवैध निर्माण कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए।

एडीसी ने कहा कि अवैध कॉलोनियों का उभरना न केवल शहरी विकास के लिए चुनौती है, बल्कि यह आम नागरिकों के लिए भी समस्याओं का कारण बनता है। इसलिए प्रशासन की यह प्राथमिकता होनी चाहिए कि ऐसी गतिविधियों पर समय रहते अंकुश लगाया जाए।

बैठक में जिला नगर योजनाकार (डीटीपी) गुंजन वर्मा ने पुलिस विभाग से अनुरोध किया कि अवैध कॉलोनियों के विरुद्ध कार्रवाई के दौरान पुलिस बल की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, ताकि कार्रवाई में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो। उन्होंने यह भी कहा कि तोड़फोड़ की कार्रवाई में होने वाले खर्च की वसूली संबंधित तहसीलदार के माध्यम से जल्द करवाई जाए और सेल डीड की पीडीएफ तैयार करवाकर विभाग को उपलब्ध कराई जाए।

डीटीपी गुंजन वर्मा ने बताया कि जिला नगर योजनाकार विभाग अवैध कॉलोनियों और अवैध निमार्णों के विरुद्ध नियमित रूप से कार्रवाई कर रहा है। किसी भी स्तर पर कोताही नहीं बरती जा रही है। अवैध निर्माण करवाने वालों के विरुद्ध मुकदमे भी दर्ज करवाए जा रहे हैं।

बैठक में एसडीएम अनुभव मेहता, डीएफओ पवन शर्मा, एडीटीपी मोहित, बिजली विभाग के कार्यकारी अभियंता, नगरपालिका सचिव, और इंफोर्समेंट थाना के इंचार्ज सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में अधिकारियों ने मिलकर यह तय किया कि विभागों के बीच समन्वय बनाकर अवैध निर्माण पर सख्ती से रोक लगाई जाएगी और दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।

नशे को जड़ से खत्म करने के लिए सभी विभाग आपसी तालमेल से करें कार्य: एडीसी सोनू भट्ट

एसबी विशेष संवाददाता

करनाल। एडीसी सोनू भट्ट ने कहा कि नशा एक गंभीर सामाजिक बुराई है, जो युवाओं के भविष्य को अंधकार की ओर धकेल रही है। नशे पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए जरूरी है कि संबंधित विभाग आपसी तालमेल और तत्परता के साथ काम करें और मिलकर एक संयुक्त अभियान चलाकर नशे को जड़ से खत्म किया जाए। वे बुधवार को लघु सचिवालय के सभागार में आयोजित जिला स्तरीय नार्को समन्वय (एनकॉर्ड) बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में जिले के विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। एडीसी ने कहा कि नशे से सर्वाधिक प्रभावित गांवों की पहचान कर वहां व्यापक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। उन्होंने कहा कि युवाओं, खासकर स्कूल और कॉलेजों में पढ़ रहे छात्रों को नशे के प्रति जागरूक करने के लिए स्टोरी बेस्ड थीम पर आधारित गतिविधियों का आयोजन जरूरी है, जिससे संदेश सीधे और प्रभावी तरीके से पहुंच सके। स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए गए कि वे मेडिकल स्टोरों पर विशेष निगरानी रखें, जो नशीली दवाइयों की बिक्री करते हैं। समय-समय पर इन दुकानों के क्रय-विक्रय का रिकॉर्ड चेक किया जाए और संदिग्ध गतिविधियों पर तुरंत कार्रवाई की जाए। शिक्षा विभाग को निर्देशित किया गया कि किसी भी स्कूल या कॉलेज के 200 मीटर के दायरे में सिगरेट, तंबाकू, गुटखा जैसे नशीले पदार्थों की दुकानों की अनुमति न दी जाए। यदि कहीं ऐसे उत्पादों की बिक्री होती पाई जाती है, तो तुरंत पुलिस को सूचित कर आवश्यक कार्रवाई की जाए। एडीसी सोनू भट्ट ने पुलिस विभाग को भी निर्देश दिए कि नशा बेचने वालों की पहचान कर उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए।

एचटेट की परीक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट

■ डीसी प्रीति व एसपी आस्था मोदी ने किया परीक्षा केंद्रों का दौरा

एसबी ब्यूरो प्रमुख/निर्मल कुमार

कैथल। हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा को लेकर डीसी प्रीति व एसपी आस्था मोदी ने संयुक्त रूप से विभिन्न परीक्षा केंद्रों का दौरा किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने सबसे पहले जाट एजुकेशन शिक्षण संस्थान, जाट कालेज तथा आरकेएसडी कॉलेज के परीक्षा केंद्रों में पहुंची। जहां उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे, जैमर, उपस्थिति व अनुपस्थिति परीक्षार्थियों की संख्या आदि के बारे में जानकारी ली। उन्होंने बायोमैट्रिक हाजिरी तथा अभ्यर्थियों की तलाशी की प्रक्रिया का भी अवलोकन किया। उन्होंने परीक्षा केंद्र अधीक्षक को निर्देश दिए कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की हिदायतों का शत प्रतिशत पालन सुनिश्चित किया जाए।

उन्होंने बताया कि जिले में कुल 25 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। पूरा प्रशासनिक अमला अलर्ट पर है। परीक्षा को निष्पक्ष, पारदर्शी एवं नकल रहित आयोजित करवाने के लिए सभी परीक्षा केंद्रों पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं। इसके साथ साथ उड़नदस्तों का भी गठन किया गया, जिन्होंने परीक्षा केंद्रों पर जाकर परीक्षा के संचालन का जायजा लिया।

इसके साथ ही सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या मोबाइल आदि परीक्षा केंद्र के अंदर ले जाने पर पाबंदी रही। अभ्यर्थियों को केन्द्र के मुख्य द्वार पर मेटल डिटेक्टर से तलाशी, बायोमेट्रिक हाजिरी सुनिश्चित की गई। एसपी आस्था मोदी ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिसकर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

परीक्षा नोडल अधिकारी एसडीएम अजय सिंह ने परीक्षा पूर्व सभी तैयारियों की समीक्षा की और सभी परीक्षा केंद्रों का स्वयं दौरा किया। उन्होंने सभी ड्यूटी मजिस्ट्रेट को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। प्रश्न पत्रों को ट्रेजरी से लेकर परीक्षा केंद्र तक ले जाने की पूरी प्रक्रिया की मॉनिटरिंग की। उन्होंने स्वयं सीसीटीवी कैमरों आदि को चैक किया।

मक्का भविष्य की नगदी फसल, किसानों को फायदा ही फायदा

आईआईएमआर व सीसीएसएचएयू द्वारा हरियाणा में मक्का की टिकाऊ खेती हेतु प्रशिक्षण का तीसरा दिन

एसबी विशेष संवाददाता/मदन पुरी

करनाल। भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान (आईआईएमआर), लुधियाना एवं क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय (सीसीएसएचएयू), करनाल के तत्वाधान में खाद्य एवं कृषि संगठन संयुक्त राष्ट्र (एफएओ), रोम द्वारा वित्त पोषित परियोजना "हरियाणा और पंजाब के चयनित ब्लॉकों में मक्का की टिकाऊ खेती से संबंधित तकनीकी सहायता एवं किसानों का क्षमता निर्माण" के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रमों के तीसरे दिन का आयोजन सफलता पूर्वक सम्पन्न हुआ।

करनाल जिले के इंद्री ब्लॉक के हलवाना, बयाना और बीर बादसों गांवों में किसानों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें 120 से अधिक किसानों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का उद्देश्य किसानों को मक्का की उन्नत विधियों, टिकाऊ और पर्यावरण-अनुकूल पद्धतियों से अवगत कराना है।

वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं परियोजना प्रमुख अन्वेषक डॉ. एस.एल. जाट ने किसानों को विभिन्न आधुनिक तकनीकों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि "विश्व में खाद्यान्न फसलों में मक्का का पहला स्थान है क्योंकि अमेरिका, चाइना, ब्राजील जैसे देशों में मक्का का उत्पादन अधिक होता है। अकेले अमेरिका 390 मिलियन टन से भी अधिक मक्का का उत्पादन करता है जो भारत के कुल खाद्यान्न फसलों के उत्पादन से अधिक है।" मक्का की पैदावार बढ़ाने के लिए समय पर खरपतवार व पोषक तत्व प्रबंधन आवश्यक है जो मक्का की गुणवत्ता और उत्पादकता में उल्लेखनीय सुधार करता है। सीसीएसएचएयू, हिसार के क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान, करनाल के डॉ. हरमिंदर, पैथोलॉजिस्ट ने मक्का में प्रमुख बीमारियों की पहचान एवं उनके एकीकृत प्रबंधन उपायों की जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि देश के साथ हरियाणा में भी मक्का उगाना समय की जरूरत है।

सीसीएसएचएयू, करनाल के डॉ. नरेंद्र सिंह, एग्रोनॉमिस्ट ने मक्का फसल में पोषक तत्व की कमी, उनका प्रबंधन, और समन्वित नियंत्रण विधियों पर विस्तृत जानकारी प्रदान की। आईआईएमआर के निदेशक डॉ. एच.एस. जाट ने अपने संदेश में कहा कि "वर्तमान में भारत में लगभग 42 मिलियन टन से अधिक मक्का का उत्पादन हो रहा है लेकिन भारत में एथेनॉल की अधिक मांग बढ़ने से आने वाले कुछ सालों में मक्का के स्तर को भी बढ़ाने की आवश्यकता है।" कार्यक्रम में डॉ. मनीष ककरालिया, रिसर्च एसोसिएट ने बताया कि मक्का पर्यावरण के लिए और पानी की बचाने हेतु अच्छा विकल्प है। किसानो धान की फसल की जगह मक्का लगाकर ग्रीन हाउस गैस जैसी गैसों के नुकसान को कम करके कार्बन क्रेडिट से अतिरिक्त मुनाफा कमा सकता है। इसमें आईआईएमआर से यंग प्रोफेशनल शुभम सैनी की भी सक्रिय भागीदारी रही। उन्होंने किसानों से संवाद कर उन्नत तकनीकों और स्थायी कृषि अभ्यासों की जानकारी साझा की।

नेशन के लिए सुलह अभियान जिला करनाल में न्यायिक इतिहास की नई पहल: इरम हसन

एसबी विशेष संवाददाता

करनाल। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव डा. इरम हसन ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा-निर्देशन में पूरे देशभर में चल रहे नेशन के लिए सुलह अभियान में जिला करनाल ने न्यायिक सुधारों की एक नई मिसाल कायम की है। इस अभियान का उद्देश्य अदालतों में वर्षों से लंबित मामलों का मध्यस्थता (मेडिएशन) के माध्यम से त्वरित, निःशुल्क और सौहार्दपूर्ण समाधान सुनिश्चित करना है।

उन्होंने बताया कि एक विशेष पहल करते हुए जिला के सभी सरकारी विभागों के प्रमुखों एवं बार एसोसिएशन के अध्यक्ष को औपचारिक पत्र जारी किए गए हैं, जिनमें उनसे आग्रह किया गया है कि वे विभागों से संबंधित ऐसे मामलों की पहचान करें जिनमें आपसी सहमति से समाधान संभव हो। इन मामलों को प्राथमिकता के आधार पर मिडिएशन सेंटर में भेजा जा रहा है। इसके अतिरिक्त, आम जनता को भी इस अभियान को भी जोड़ा गया है। नागरिकों से अपील की गई

है कि वे अपने व्यक्तिगत, पारिवारिक, संपत्ति, या लेन-देन से जुड़े लंबित विवादों को मध्यस्थता के माध्यम से निपटाने के लिए पहल करें और संबंधित न्यायिक अधिकारी से केस मिडिएशन में भेजने का निवेदन करें।

उन्होंने बताया कि मध्यस्थता प्रक्रिया की विशेषताएं यह प्रक्रिया पूरी तरह निःशुल्क है किसी भी प्रकार की फीस नहीं ली जाती, गोपनीयता सुनिश्चित रहती है। कोई सार्वजनिक कार्यवाही नहीं होती, निर्णय दोनों पक्षों की आपसी सहमति से होता है कोई हार-जीत नहीं, सिर्फ समाधान, न्याय में देरी नहीं, बल्कि कुछ ही बैठकों में स्थायी समझौता। अभियान की प्रभावशीलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अब तक सैकड़ों नागरिकों ने इस व्यवस्था का लाभ उठाकर वर्षों पुराने मामलों का सौहार्दपूर्ण निपटारा किया है, जिनमें पारिवारिक विवाद, संपत्ति विवाद, घरेलू हिंसा, सेवा विवाद, और चेक बाउंस जैसे कई गंभीर मामले शामिल हैं।

मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव डा. इरम हसन ने यह अभियान केवल मामलों का निपटान नहीं, बल्कि सामाजिक संबंधों की मरम्मत और पुनः विश्वास निर्माण की दिशा में एक सकारात्मक प्रयास है। हर व्यक्ति न्याय तक सरलता से पहुंचे, बिना डर और बिना भेदभाव के इस प्रयास ने न्यायिक प्रणाली को केवल कागजों की कार्यवाही तक सीमित न रखते हुए जनहित से जोड़ने का कार्य किया है, जिससे अदालतों पर दबाव भी घटा है और जनता को राहत भी मिली है।

शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई एचटेट लेवल-3 की परीक्षा, 3742 अभ्यर्थी हुए शामिल

एसबी विशेष संवाददाता/मदन पुरी

करनाल। हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा (एचटेट) के अंतर्गत बुधवार को आयोजित लेवल-3 (पीजीटी) की परीक्षा जिले में शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुई। उपायुक्त उत्तम सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि परीक्षा 14 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई, जिसमें कुल 4255 पंजीकृत अभ्यर्थियों में से 3742 ने परीक्षा दी, जबकि 513 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे।

डीसी ने बताया कि अगली परीक्षाएं 31 जुलाई को करनाल जिले में आयोजित की जाएंगी। इस दिन दो सत्रों में लेवल-2 (टीजीटी) और लेवल-1 (पीआरटी) की परीक्षाएं होंगी। प्रातः कालीन सत्र में एचटेट लेवल-2 की परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक आयोजित की जाएगी, जबकि

■ 31 जुलाई को लेवल-1 और लेवल-2 की परीक्षाएं आयोजित होंगी-डीसी उत्तम सिंह

सायं कालीन सत्र में लेवल-1 की परीक्षा दोपहर 3 बजे से सायं 5:30 बजे तक होगी। डीसी उत्तम सिंह ने बताया कि लेवल-1 की परीक्षा के लिए जिले में 9 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां 2562 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। वहीं, लेवल-2 की परीक्षा 22 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी, जिसमें 6729 अभ्यर्थी भाग लेंगे।

उपायुक्त ने अभ्यर्थियों से अपील की कि वे परीक्षा के दिन किसी भी प्रकार के मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच या अन्य डिजिटल उपकरण लेकर परीक्षा केंद्र में न आएं। उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसे उपकरणों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा और सभी अभ्यर्थियों की प्रवेश से पहले जांच की जाएगी। साथ ही परीक्षा ड्यूटी में तैनात कर्मियों को भी बिना पहचान पत्र के केंद्र में प्रवेश नहीं मिलेगा। डीसी ने अभ्यर्थियों से समय पर परीक्षा केंद्र पहुंचने की अपील की ताकि प्रक्रिया सुचारू रूप से संपन्न हो सके। उन्होंने सभी केंद्राधीक्षकों और ड्यूटी स्टाफ को निर्देश दिए कि परीक्षा के दौरान पूरी सतर्कता बरती जाए और किसी भी प्रकार की लापरवाही न हो।

एचटेट परीक्षाओं को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और शांतिपूर्ण व निष्पक्ष परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध किए गए हैं।

प्रस्तावित कलेक्टर रेट को लेकर सुझाव व आपत्ति आमंत्रित

एसबी ब्यूरो प्रमुख/निर्मल कुमार

कैथल। डीसी प्रीति ने बताया कि जिला कैथल की सभी तहसीलों एवं उप तहसीलों में वर्ष 2025-26 (एक अगस्त 2025 से 31 मार्च 2026) प्रस्तावित कलेक्टर रेट निर्धारित किए जाने हैं। यह प्रास्तावित रेट विभागीय वैबसाइट http://kaithal.gov.in पर उपलब्ध हैं। यदि किसी को कोई सुझाव या आपत्ति है हो तो 31 जुलाई 2025 तक संबंधित उपमंडल अधिकारी कैथल या राजस्व अधिकारी कैथल की ईमेल droktl.hry@gmail.com पर या स्वयं कार्यालय में आकर दे सकता है।

उपायुक्त कैथल प्रीति।

राजौंद में रक्तदान शिविर का होगा आयोजन

एसबी संवाददाता

राजौंद। ब्रह्मकुमारी आश्रम राजौंद प्रभारी बीके आशा ने बताया कि राजौंद में रक्तदान शिविर का आयोजन होने जा रहा है। नागरिकों से रक्तदान शिविर में बढ़-चढ़ कर भाग लेने की अपील की गई है। बताया गया कि नगर के कैथल मार्ग पर स्थित प्रजापिता ब्रह्माकुमारी आश्रम राजौंद में तिथि:24 अगस्त को रक्तदान शिविर का आयोजन होगा। सभी क्षेत्रवासियों, नागरिको, रक्तदानी, मानव व राष्ट्र प्रेमियों को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय आश्रम कैथल रोड-राजौंद, जिला कैथल में ब्लड डोनेशन कैम्प में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है।

बताया गया कि रक्तदान करने के इच्छुक अपना रजिस्ट्रेशन करवा कर कैम्प में भाग ले सकते है। प्रवक्ता ने बताया कि इस कैम्प में भाग लेने वाले भाई बहनो को दीदी के हाथों से ईश्वरीय सोगात व सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। कैम्प का समय सुबह 9:00 बजे से दोपहर बाद 1:00 बजे तक रहेगा।

गांव सौंगल में नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, पुलिस जांच में जुटी

एसबी ब्यूरो

राजौंद। नव विवाहिता की मौत की खबर से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। राजौंद खंड के गांव सौंगल में नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। आयु तकरीबन 20 वर्षीय कमलजीत कौर दो महीने पहले पटियाला के गांव से लव मैरिज कर गौरव पुत्र सत्यवान, जिला कैथल के गांव सौंगल आई थी। मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का गंभीर आरोप लगाया है, जबकि ससुराल पक्ष ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए झूठा करार दिया है। सूचना पाकर राजौंद पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। मृतका की

मृतका की फाइल फोटो।

मां ने ससुरालियों पर हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। मृतका के ससुर ने सभी आरोपों को निराधार बताया है। जांच अधिकारी ने बताया कि कमलजीत कौर पटियाला के नजदीकी गांव की रहने वाली थी और उसने कुछ महीने पहले सोंगल निवासी युवक से प्रेम विवाह किया था।

पुलिस ने प्रारंभिक जांच के आधार पर ससुराल पक्ष के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के साथ आगे की जांच जारी है। यह घटना क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है और पुलिस मामले की तह तक जाने के लिए सभी पहलुओं की जांच कर रही है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति छात्रों को ज्ञान के साथ कौशल भी दे, यही हमारा लक्ष्य है-शिक्षा मंत्री

संजना भारती/विज्ञप्ति द्वारा

चंडीगढ़। हरियाणा के शिक्षा मंत्री श्री महिपाल ढांडा ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी-2020) का उद्देश्य छात्रों को केवल किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि व्यावसायिक कौशल भी देना है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के विजन को साकार करने में शिक्षा की बड़ी भूमिका है, और एनईपी इसमें एक मजबूत आधार बनेगी।

गुरुग्राम यूनिवर्सिटी, गुरुग्राम में आयोजित एक बैठक में शिक्षा मंत्री ने यूनिवर्सिटी में एनईपी 2020 के क्रियान्वयन की समीक्षा की। बैठक में वाइस चांसलर श्री संजय कौशिक, मुख्यमंत्री के ओएसडी श्री राज नेहरू, कुलसचिव श्री संजय अरोड़ा, सभी डीन और चेयरपर्सन उपस्थित रहे।

शिक्षा मंत्री ने शिक्षकों से सीधा संवाद करते हुए विभागीय गतिविधियों की जानकारी ली। उन्होंने यह जानना चाहा कि किस विभाग में कितने विद्यार्थी अध्ययनरत हैं, उन्हें किस प्रकार मार्गदर्शन और प्रेरणा दी जा रही है, और वे किस तरह करियर के लिए तैयार हो रहे हैं। मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि शिक्षकों की भूमिका केवल पढ़ाने तक सीमित न रहे, बल्कि वे छात्रों के समग्र विकास में योगदान दें। यूनिवर्सिटी के वरिष्ठ अधिकारियों ने जानकारी दी कि गुरुग्राम यूनिवर्सिटी और इससे सम्बद्ध सभी कॉलेजों में एनईपी को प्रभावी रूप से लागू कर दिया गया है। उन्होंने मंत्री को अवगत करवाया कि क्रेडिट आधारित पाठ्यक्रम, मल्टीपल एंट्री-एग्जिट प्रणाली, स्किल-आधारित कोर्स, इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग, स्टार्टअप, इन्क्यूबेशन सेंटर, प्लेसमेंट, इंटर्नशिप, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और करियर काउंसलिंग जैसी कई पहलों पर काम किया जा रहा है।

शिक्षा मंत्री ने शिक्षकों को सुझाव दिया कि वे बड़ी इंडस्ट्रीज के साथ समझौता करें ताकि छात्रों को पढ़ाई के दौरान ही व्यावसायिक अनुभव मिल सके और वे सीधे नौकरी के लिए तैयार हो सकें।